@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

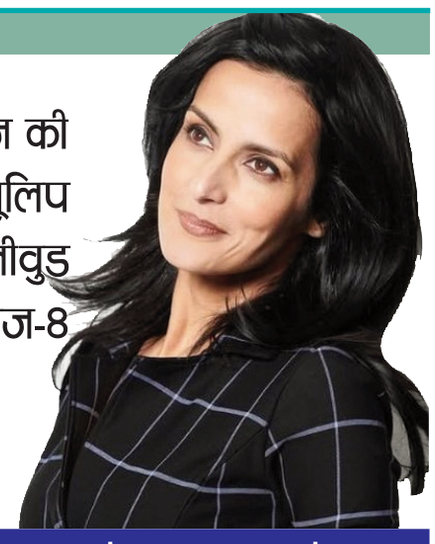

यशराज की फिल्म से ट्यूलिप जोशी का बॉलीवुड डेब्यू...पेज-8

नई दिल्ली, शुक्रवार, 11 सितंबर 2026, वर्ष-1, अंक-284, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

आईआरसीटीसी धनशोधन मामला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत नौ के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और छह अन्य के खिलाफ धन शोधन के आरोप तय करने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 16 आरोपियों में से सात को आरोप मुक्त कर दिया और नौ के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आदेश के मुख्य हिस्सों को मौखिक रूप से सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि इस समय आपराधिक इरादे या अपराध करने की मानसिक स्थिति का पता लगाने के कड़े मानकों की जरूरत नहीं है और अदालत को केवल यह देखना है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई पुख्ता संदेह है।

अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज इसी कथित घोटाले के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख और 11 अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किये थे। न्यायाधीश गोगने ने कहा कि धन शोधन के अपराध के मामले में सात लोगों के खिलाफ ''पुख्ता संदेह'' है तथा जांच का स्वरूप, समय और तरीका -- ऐसा नहीं लगता कि यह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो, जैसा कि आरोपियों के वकीलों ने

दलील दी है। अदालत ने कहा, कुछ संदिग्ध सौदे असल में सबके सामने किए जाते हैं, जहां आम लोगों की मौजूदगी असलियत जानने के बजाय उसे छिपाने का काम करती है।

अदालत इस बात पर खास तौर पर गौर करेगी कि सीबीआई और पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) मामलों, खासकर सांसद और विधायक (एमपी/एमएलए) से जुड़े मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत का उद्देश्य ही ऐसे छिपे हुए और अनैतिक सौदों का पता लगाना है, जिनमें निजी फायदे के लिए जनता के भरोसे और संपत्ति का सौदा किया जाता है। अदालत ने कहा कि 2005 से 2014 के बीच की अवधि से जुड़े ईडी के आरोपों से साफ पता चलता है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के कहने पर रेलवे अधिकारियों ने रांची और ओडिशा के पुरी में होटलों का पट्टा सुजाता होटल को देने के लिए निविदा में हेर-फेर की थी। अदालत ने कहा, इसके बदले में, सुजाता होटल के निदेशक विनय कोचर और विजय कोचर ने पटना में अपनी बेशकीमती जमीन डीएमसीपीएल नाम की कंपनी को बहुत औने-पौने दाम पर हस्तांतरित कर दी। इस कंपनी का संचालन लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी प्रेम चंद (पीसी) गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता करते थे। अदालत ने यह भी कहा कि बाद में सरला गुप्ता और अन्य लोगों ने इस कंपनी के शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बहुत कम कीमत पर हस्तांतरित कर दिए। अदालत ने कहा, इस लगभग मुफ्त जमीन की देखरेख करने वाली नयी कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी है।

इस बारे में पुख्ता संदेह है कि लालू प्रसाद ने अपने पद का दुरूपयोग करके अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के लिए गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित की, और वे पटना के एक महंगे वाणिज्यिक इलाके में मौजूद इस जमीन को उपयोग में लाते रहे। अदालत ने कहा कि पटना स्थित यह जमीन अपराध की आय से अर्जित संपत्ति है और लारा प्रोजेक्ट्स, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, पी.सी. गुप्ता, सरला गुप्ता, विजय कोचर और विनय कोचर के खिलाफ धन शोधन का आरोप तय किया जा सकता है।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, हालांकि, अदालत को आरोपी गौरव गुप्ता, नाथ मल काकरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, राजीव कुमार रेलन और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले। अदालत ने कहा, नौ आरोपियों पर आरोप तय किए जा रहे हैं। सात को आरोप मुक्त कर दिया गया है। निर्देश दिया जाता है कि पीएमएलए की धारा 3 (धन शोधन का अपराध) और धारा 4 (धन शोधन के लिए सजा) के तहत आरोपियों पर आरोप तय किए जाएं।

सार समाचार

एमसीडी ने तीन अभियंताओं को निलंबित किया

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही के आरोप में भवन विभाग के एक सहायक अभियंता और दो कनिष्ठ अभियंताओं को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे पहले निगम ने सत्य निकेतन में पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास वाली एक बहुमंजिला इमारत ढहने के बाद सोमवार को अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने तक दक्षिण क्षेत्र के उपायुक्त (डीसी) राकेश कुमार और चार अभियंताओं को निलंबित कर दिया था। इस हादसे में पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गए थे।

झारखंड के तीन इनामी नक्सलियों ने बंगाल में किया सरेंडर

रांची,एजेंसी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में करीब दो दशक से सक्रिय 15 लाख रुपये के इनामी माओवादी रामप्रसाद मार्डी उर्फ सचिन और उसकी 10 लाख रुपये की इनामी पत्नी मीता उर्फ नयनतारा ने बंगाल में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनके अलावा इनामी महिला कैडर बुलू उर्फ गौरी ने भी सरेंडर किया है। इन्होंने पुलिस को एके-47 सहित कई हथियार भी सौंपे हैं। बंगाल पुलिस की ओर से फिलहाल आधिकारिक तौर पर इन तीनों के सरेंडर का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन झारखंड पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड के झुंझका गांव का रहने वाला रामप्रसाद मार्डी पिछले करीब 20 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय था।

देशभर में डीआरआई की कार्रवाई में 41 किलो विदेशी सोना जब्त

नई दिल्ली,एजेंसी। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने संगठित सोना तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हाल के दिनों में देशभर में छह अलग-अलग अभियानों में करीब 41 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 62 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को बताया गया कि डीआरआई की इन कार्रवाइयों में तीन विदेशी नागरिकों समेत कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में हवाई अड्डों, रेल मार्गों और भारत-बंगलादेश सीमा के जरिए संचालित संगठित तस्करी नेटवर्क तथा सोना छिपाने के नये तरीकों का खुलासा हुआ है।

शक्तिशाली लोगों के हिंसक होने का फैशन बन गया है : राहुल

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर के दिवंगत संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह को न्याय दिलाने का संकल्प लिया और कहा कि आजकल यह एक तरह का फैशन बन गया है कि यदि कोई शक्तिशाली है तो वह हिंसक और अहंकारी हो सकता है तथा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है।

उन्होंने यह टिप्पणी मणिपुर के दिवंगत संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के सम्मान में आयोजित एक स्मृति कार्यक्रम में कही। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा का जवाब गुस्से और नफरत से नहीं, बल्कि अपनी बात मजबूती से रखने और उस विचार के समर्थन से दिया जाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति विश्वास करता है। विक्रम सिंह की दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के किलोकरी गांव में बीते रविवार को कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने कहा, यह एक त्रासदी है कि एक युवा व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यह भी त्रासदी है कि उन पर इसलिए हमला किया गया कि उनका ताल्लुक किसी क्षेत्र (मणिपुर) से था। यह मणिपुर के लोगों के लिए भी त्रासदी है। उनका कहना था कि घटना में हिंसा, नफरत और अहंकार था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा,आजकल यह एक तरह का फैशन बन गया है कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप हिंसक हो सकते हैं। अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप अहंकारी हो सकते हैं और किसी तरह आप वह सब कर सकते हैं, जो आपका मन करे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति का जवाब गुस्से या नफरत से नहीं दिया जाना चाहिए।

बैंक कर्मचारियों की आज देशव्यापी हड़ताल, कामकाज होगा प्रभावित

नई दिल्ली, एजेंसी। बैंक कर्मचारी संगठनों ने पांच दिन का कार्यदिवस लागू करने समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी और जमा समेत अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

हड़ताल के कारण देश के कई हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं चार दिन तक प्रभावित रह सकती हैं। 11 सितंबर को शुक्रवार है और इसके बाद के दो दिन बैंकों में अवकाश हैं। कुछ राज्यों में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के कारण अवकाश रहेगा। इस बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को हड़ताल के कारण कामकाज पर संभावित असर की जानकारी दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को जारी सूचना में कहा, हमने हड़ताल के दिन शाखाओं और कार्यालयों का सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।

चिनफिंग, पुतिन और पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे मोदी

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 30 देशों और संगठनों के प्रमुख लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली, एजेंसी।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। यह बीते सात साल में उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इसे व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर बनाने के एक अहम मौके के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। यह बातचीत ऐसे समय में होगी, जब दुनिया भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। चिनफिंग की भारत की दो दिवसीय यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुई कई उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद हो रही है। इनमें बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भी शामिल है।

यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पुतिन के साथ बातचीत शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे, जबकि पेजेश्कियान के साथ शाम 6:15 बजे होनी है। चिनफिंग के साथ सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक जारी सैन्य गतिरोध के कारण बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों पक्षों ने पिछले एक साल में विश्वास बहाली के कई कदम

उठाए हैं। शनिवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली शामिल हैं। हालांकि, शनिवार को मोदी और चिनफिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पश्चिमी एशिया में जारी संकट और यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों के साथ मॉस्को के तनाव को देखते हुए शुक्रवार को पुतिन और पेजेश्कियान के साथ प्रस्तावित प्रधानमंत्री की बैठकें भी उतनी ही अहम मानी जा रही हैं।

मामले से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि बैठक में मोदी और चिनफिंग के वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर मौजूदा हालात की समीक्षा करने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों के तहत व्यापार और निवेश बढ़ाने समेत सहयोग के और रास्ते तलाशने पर भी चर्चा कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, चिनफिंग शनिवार को दिल्ली पहुंचेंगे और मोदी के साथ उनकी बैठक उसी दिन शाम छह बजे होनी है। मोदी और चिनफिंग ने पिछले साल 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की थी।

अधिकारियों के अनुसार, मोदी-पुतिन की बैठक में रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल और लोगों के आदान-प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। क्रेमलिन (रूस के राष्ट्रपति का आधिकारित आवास और कार्यालय) के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कहा था कि दोनों पक्ष ब्रह्मोस मिसाइल को उन्नत करने पर भी विचार कर रहे हैं।

विशेष रात्रिभोज में भारत एवं अन्य देश के कलाकार देंगे प्रस्तुति

नई दिल्ली,एजेंसी। 'ब्रिक्स' के अन्य सदस्य देशों के कलाकारों के साथ मुख्य रूप से भारत के 100 से अधिक कलाकारों का एक समूह उस विशेष रात्रिभोज में प्रस्तुति देगा जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर विभिन्न देशों के नेताओं के लिए करेंगे। इस मामले से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी। भारत 12-13 सितंबर को मध्य दिल्ली स्थित विशाल भारत मंडपम में 'ब्रिक्स' शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों सहित कई शीर्ष गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।

मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा, कलाकारों का एक बड़ा दल (जिसमें मुख्य रूप से भारत के शास्त्रीय नर्तक और संगीतकार तथा ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के संगीतकार शामिल होंगे) 12 सितंबर को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर भारत मंडपम में प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में 'ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्यक्रम' प्रस्तुत करेगा।'' उन्होंने बताया कि इस कलाकार समूह में करीब 160 सदस्य होंगे, जिसमें भारतीय नर्तक और संगीतकार प्रस्तुति दल का मुख्य हिस्सा होंगे।

ब्रिक्स सम्मेलन: दिल्ली बंद नहीं होगी, रोका जा सकता है यातायात

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कोई पूर्ण बंदी नहीं होगी, लेकिन उन सड़कों पर कुछ वक्त के लिए यातायात को रोकने, मार्ग परिवर्तन और प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं जहां से अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीवीआईपी) की गाड़ियों का काफिला गुजरेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि सुरक्षा आवश्यकताओं और गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही के आधार पर इन व्यवधानों की अवधि तय होगी। यातायात पुलिस ने 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले एक विस्तृत परामर्श जारी किया।

अधिकारियों ने बताया कि विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही से जुड़े यातायात प्रतिबंध 10 सितंबर से लगभग 14 सितंबर तक लागू रहने की संभावना है।

यातायात पुलिस ने कहा कि अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों और वीआईपी आवाजाही के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन जहां भी सुरक्षा व्यवस्था अनुमति देगी, सामान्य यातायात जारी रहेगा। पुलिस ने कहा कि नियंत्रित क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को सुरक्षा व्यवस्था के अधीन आवाजाही की अनुमति होगी और उन्हें वैध पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण साथ रखने एवं वहां तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

पुलिस ने कहा कि वीआईपी आवाजाही के दौरान यातायात रोकने की कोई निश्चित अवधि नहीं है। सुरक्षा आवश्यकताओं और मौके की स्थिति के आधार पर यातायात को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है या मार्ग बदला जा सकता है।

शहर में बुधवार शाम को इस व्यवधान की एक झलक तब देखने को मिली जब गाड़ियों के काफिले की आवाजाही की 'रिहर्सल' के कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। उनका दावा है कि चंद मिनटों में पूरे होने वाले रास्ते को तय करने में घंटों का वक्त लग रहा है।

संशोधित नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को कीमत में कटौती की घोषणा करते समय कम की गई कीमत के साथ 'पूर्व कीमत' भी बतानी होगी

ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती, फर्जी छूट और छुपे चार्ज पर लगेगी रोक

नई दिल्ली,एजेंसी।

सरकार ने कीमतों में पारदर्शिता, किसी उत्पाद को प्रमुखता से दिखाने (स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग) पर रोक, खोज परिणामों में हेरफेर और भ्रामक तौर-तरीकों (डार्क पैटर्न) से जुड़े नियमों को सख्त करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन किया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने यह जानकारी दी।

विभाग के बयान के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 एक जनवरी, 2027 से लागू होगा।

संशोधित नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को कीमत में कटौती की घोषणा करते समय कम की गई कीमत के साथ 'पूर्व कीमत' भी बतानी होगी। 'पूर्व कीमत' से आशय उस कीमत से है जिस पर छूट की घोषणा से पहले के 30 दिन में उत्पाद की पेशकश सबसे कम कीमत पर की गई थी। नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे खोज परिणामों में हेरफेर करने से रोक दिया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को गुमराह करते हों या खोज से संबंधित सवाल के लिए परिणामों की प्रासंगिकता को प्रभावित करते हों।

बयान में कहा गया कि प्रायोजित सूचीबद्धता (किसी उत्पाद को अन्य की तुलना में प्राथमिकता से दिखाने) की पहचान स्पष्ट और प्रमुख रूप से करनी होगी।

विभाग ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को भ्रामक तौर-तरीकों (डार्क पैटर्न) की रोकथाम और

नियमन के लिए 2023 में जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

भ्रामक तौर-तरीकों से आशय ऐसे डिजाइन या कारोबारी तरीकों से है, जिनके जरिये उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई विकल्प चुनने, खरीदारी करने या निर्णय लेने के लिए प्रभावित या गुमराह किया जाता है। ई-कॉमर्स कंपनियों को हर साल अपना स्व-मूल्यांकन करना होगा और अनुपालन प्रमाणपत्र भी प्रदर्शित करना होगा। संशोधित नियमों के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनी को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) की 'कन्वर्जेंस' प्रक्रिया में भागीदार बनना होगा। विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 2025 में कुल 17,71,622 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 5,11,196 यानी करीब 29 प्रतिशत शिकायतें ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित थीं। नियमों के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियों को शिकायतकर्ता को उनके शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी। नियमों के मुताबिक, मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ताओं को सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करने के लिए 'बेस्ट बिफोर' या 'यूज बिफोर' तारीख तथा रिटर्न, रिफंड, वारंटी, डिलिवरी और भुगतान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी।

विभाग ने कहा कि आयातित वस्तुओं के मामले में आयातक का विवरण और वस्तु के मूल देश की जानकारी भी देनी होगी।

नियमों में मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ताओं के ब्योरे का निर्धारित उद्देश्यों के लिए स्पष्ट और सकारात्मक सहमति के बिना इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स मंच आपूर्ति से इतर सेवाओं के लिए एक-साथ जोड़कर शुल्क नहीं लगा सकेंगे। हालांकि, लॉयल्टी या सदस्यता कार्यक्रम इसके अपवाद होंगे।

चांदनी चौक में आभूषण की 56 दुकानें सील

नई दिल्ली, एजेंसी।

चांदनी चौक के कूचा महाजनी इलाके में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आभूषण और सर्राफा की कम से कम 56 दुकानों को बृहस्पतिवार को सील कर दिया। कारोबारियों ने यह दावा किया और कहा कि दुकानों के अंदर करोड़ों रुपये के आभूषण रखे थे। यह कार्रवाई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना के बाद शहरभर में खतरनाक और अवैध इमारतों के खिलाफ एमसीडी की तेज की गई कार्रवाई के बीच हुई है। सत्य निकेतन हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी।

'ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने बताया कि दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए थे और बृहस्पतिवार सुबह करीब 11:30 बजे सीलिंग की कार्रवाई की गई। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, सवाल यह भी है कि सत्य निकेतन हादसे के बाद क्या केवल कारोबारियों को ही इस कार्रवाई का खामियाजा भुगतना पड़ेगा या किसी सरकारी विभाग और नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कारोबारियों के अनुसार, दुकानों पर लगाए गए नोटिस पिछली तारीख के हैं। एसोसिएशन ने एक ऐसा नोटिस साझा किया, जिस पर 12 मई, 2026 की तारीख दर्ज है। नोटिस में लिखा था, संबंधित संपत्ति के बेसमेंट के दुरुपयोग को रोकने और परिसर को 48 घंटे के भीतर मास्टर प्लान-2021 के तहत अनुमत उपयोग के दायरे में लाने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा इसे व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए सील क्यों न कर दिया जाए।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त

दिल्ली पुलिस ने विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर 15,000 पुलिसकर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की करीब 200 कंपनियों की तैनाती की है।

नई दिल्ली,एजेंसी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर 15,000 पुलिसकर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की करीब 200 कंपनियों की तैनाती की है। साथ ही वीवीआईपी आवाजाही को देखते हुए आम लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन (पीएसडी) के विशेष पुलिस आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्राध्यक्षों, सरकार प्रमुखों, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और मंत्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, यह भी हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारत मंडपम, हवाई अड्डों, विदेशी मेहमानों के ठहरने वाले होटलों और उन सभी स्थानों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जहां उनकी निर्धारित या संभावित बैठकें हो सकती हैं। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि सम्मेलन के मद्देनजर कुछ मार्गों पर निर्धारित समय के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रतिबंध केवल वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सीमित समय के लिए होंगे, किसी भी मार्ग को पूरी तरह बंद नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई एजेंसियों के साथ समन्वय किया है। वीवीआईपी रूट का सुरक्षा ऑडिट और सर्वे कराया गया है तथा किसी भी तरह की तोड़फोड़ या सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारत मंडपम में प्रवेश नियंत्रण, निगरानी, सत्यापन और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय बैठकें की गई हैं और खुफिया सूचनाओं के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे सुरक्षा अभियान के लिए लगभग 15,000 दिल्ली पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि अर्द्धसैनिक बलों की करीब 200 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई हैं। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ 10 साझेदार देशों के प्रतिनिधिमंडल तथा अन्य आमंत्रित विदेशी मेहमान भी हिस्सा ले रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर होने वाले आयोजन में हर नेता की राजधानी में केवल एक बार आवाजाही नहीं होती, बल्कि दिनभर में कई उच्च सुरक्षा वाले दौरे तय होते हैं।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली रोशनी से जगमगाई

नई दिल्ली,एजेंसी।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 से पहले नई दिल्ली क्षेत्र को भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने व्यापक सजावटी रोशनी की है। परिषद ने 17 प्रमुख गोल चक्करों, 11 होटल परिसरों और 10 प्रमुख एनडीएमसी भवनों को सजावटी रोशनी से जगमगा दिया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट और निर्धारित होटलों से भारत मंडपम तक जाने वाले प्रमुख मार्गों पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम के अनुरूप सजावट की गई है।

एनडीएमसी के अनुसार, प्रमुख गोल चक्करों में पटेल चौक, विंडसर प्लेस, मंडी हाउस, शांतिपथ-कौटिल्य, शांतिपथ-पंचशील, शांतिपथ-सत्य मार्ग, आरएमएल, तीन मूर्ति, क्लैरिजेस होटल, सम्राट होटल, अशोका होटल, गोलमेथी, लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, मानसिंह, यॉर्क प्लेस और प्रधानमंत्री राउंडअबाउट शामिल हैं। यहां पेड़ों, झाड़ियों और हरित क्षेत्रों में एलईडी, अपलाइटर और लड़ी रोशनी लगाई गई है।

इसके अलावा ताज पैलेस, आईटीसी मौर्या, अशोका, सम्राट, द लीला, ताज मानसिंह, क्लैरिजेस, शांगरी-ला, ले मेरिडियन और द इम्पीरियल समेत 11 होटल परिसरों के आसपास भी सजावटी रोशनी की गई है। इन मार्गों पर पेड़ों को भी रोशन किया गया है। एनडीएमसी के 10 प्रमुख भवनों और स्थलों पर भी सजावटी रोशनी की गई है। इनमें पालिका केंद्र, एनडीसीसी फेज-दो, कन्वेंशन सेंटर, चंद्रलोक बिल्डिंग, चरखा संग्रहालय, सेंट्रल पार्क, पालिका बाजार क्षेत्र, अटल आदर्श विद्यालय-मंदिर मार्ग, लोकनायक भवन और चाणक्य भवन शामिल हैं।

ब्रिक्स सम्मेलन की ब्रांडिंग के तहत महत्वपूर्ण मार्गों पर सड़क प्रकाश खंभों में एलईडी साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर सम्मेलन का लोगो प्रदर्शित किया गया है। वहीं, प्रकाश खंभों पर ब्रिक्स सम्मेलन के पोस्टर भी लगाए गए हैं। सड़कों के किनारे करीब 350 विद्युत पैनल बॉक्सों को भी ब्रिक्स की थीम से सजाया गया है।

गाजियाबाद में 120 उम्रदराज वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा

गाजियाबाद,एजेंसी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान जनपद में 120 ऐसे वाहनों को चिन्हित किया गया, जो निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं। इन वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके अनधिकृत संचालन पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अंकिता शुक्ला ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके डीजल वाहनों और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेट्रोल वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग की टीम ने अभियान के दौरान चिन्हित वाहनों के अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। साथ ही संबंधित वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के माध्यम से स्क्रैप कराने की प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। एआरटीओ प्रवर्तन अंकिता शुक्ला ने कहा कि अभियान का प्रमुख उद्देश्य आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और सड़कों पर ऐसे वाहनों के अनधिकृत संचालन को रोकना है।

उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों का संचालन न करें और एनजीटी तथा शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जनपद में लगातार अभियान चलाया जाएगा। 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों की जांच कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी विभाग की ओर से आमजन और वाहन स्वामियों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की गई है। अधिकारियों ने कहा कि वाहन स्वामी समय रहते आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप कराएं और शासन एवं एनजीटी के निर्देशों का पूर्ण पालन करें।

नौकरी का झांसा दे इंजीनियर से पौने सात लाख की ठगी

गाजियाबाद,एजेंसी।

जालसाज ने प्रतिष्ठित कंपनी में जीएम पद पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में रहने वाले इंजीनियर से 6.78 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी ने खुद को नौकरी डॉट कॉम का एचआर मैनेजर बताकर पीड़ित को जाल में फंसाया। ठगी का पता लगने पर पीड़ित इंजीनियर ने साइबर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की अरिहंत एंबिएंस सोसाइटी निवासी आकाश सरन लाल ने साइबर थाने में शिकायत दी कि पांच अगस्त को पृथ्वीराज सिंह नामक व्यक्ति ने कॉल और ई-मेल कर खुद को नौकरी डॉट कॉम का एचआर मैनेजर बताया।

उसने मैकिंसे कंपनी में गुरुग्राम जीएम पद खाली होने की जानकारी देकर रिज्यूम और आधार कार्ड मांगा। नौकरी की उम्मीद में आकाश ने उसी दिन दस्तावेज भेज दिए। 11 अगस्त को मैकिंसे के सिंगापुर कार्यालय के नाम से इंटरव्यू के लिए फोन आया। 12 और 13 अगस्त को भी फोन पर इंटरव्यू लिया गया। 14 अगस्त को फोन और ई-मेल से चयन की सूचना दी गई। इसके बाद जालसाजों ने कंपनी कंसल्टिंग क्षेत्र की होने का हवाला देकर ज्वाइनिंग से पहले कंसल्टिंग कोर्स करना अनिवार्य बताया और इसके नाम पर 49 हजार 800 रुपये जमा करा लिए।

पीड़ित के मुताबिक, कोर्स की रकम जमा कराने के बाद जालसाजों ने अलग-अलग प्रक्रियाओं के नाम पर लगातार भुगतान कराया। 17 अगस्त को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए 92 हजार 400 रुपये, जबकि 18 अगस्त को घर पर एआईआईएमएस की मेडिकल वैन आने की बात कहकर 1.30 लाख रुपये लिए गए। 19 अगस्त को सिंगापुर कार्यालय से दस्तावेज लाने वाले पीआरओ की व्यवस्था के नाम पर 94 हजार 600 रुपये जमा कराए गए। 21 अगस्त को कोलेटरल डिपॉजिट के नाम पर 2.61 लाख रुपये मांगे गए।

जिसे पीड़ित ने बैंक सर्वर की समस्या बताकर तीन बार में ट्रांसफर किया। 22 अगस्त को आईटी इक्विपमेंट फीस सिक्योरिटी के नाम पर 3.27 लाख रुपये और मांगे गए तो पीड़ित को शक हुआ। उन्होंने पूर्व भुगतानों और मेडिकल समेत अन्य प्रक्रियाओं का विवरण मांगा और स्पष्ट किया कि जानकारी मिलने तक कोई रकम नहीं देंगे। आरोप है कि जालसाजों ने 99 प्रतिशत प्रक्रिया पूरी होने का दावा करते हुए तत्काल भुगतान का दबाव बनाया और 25 अगस्त को मुंबई हेड ऑफिस में बैठक के बाद पूरी रकम लौटाने का भरोसा दिया।

आकाश सरन लाल के मुताबिक, जालसाजों ने 25 अगस्त को दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट भेजा, लेकिन वापसी का टिकट नहीं दिया। वापसी का टिकट मांगने पर कहा गया कि मुंबई में बैठक कितने समय चलेगी, यह तय नहीं है। इससे उनका शक गहरा गया।

पार्टनर पर लगाया दस लाख रुपये ठगने का आरोप

मुरादनगर,एजेंसी।

नगर की जीतपुर कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने पार्टनर पर साढे.दस लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नगर की जीतपुर कॉलोनी निवासी मोहसिन ने बताया कि भोजपुर थानाक्षेत्र के गांव अमराला निवासी इमरान के साथ गाड़ी के सेल परचेज का काम किया था। मोहसिन का आरोप है कि इमरान ने तीन साल का हिसाब नहीं किया और 1050000 रुपए हड़प लिए। पैसे वापस मांगने पर हत्या करने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने डीसीपी ग्रामीण को शिकायत दी थी। डीसीपी ग्रामीण ने मुरादनगर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। एसीपी मसूरी सर्किल ने बताया कि तहरीर के आधार पर इमरान निवासी गांव अमराला थाना भोजपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

सरकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी आज हड़ताल पर

गुरुग्राम,एजेंसी।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को सरकारी बैंकों के सभी अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इससे बैंकों में लेनदेन न होने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।सिविल लाइंस के पीएनबी परिसर में शुक्रवार को बैंकों के कर्मचारी-अधिकारी मांगों को प्रदर्शन करेंगे। यूएफबीयू संयोजक दीपक गौतम ने कहा कि 11 सितंबर को एक दिन की हड़ताल के बाद 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। मांगें पूरी न होने पर 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है।

उनकी मांगों में सप्ताह में पांच दिन काम (सभी शनिवार अवकाश), प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में संशोधन और पेंशन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

आईजीआई हवाईअड्डे पर तीस किलो से अधिक गांजा पकड़ा गया

नई दिल्ली,एजेंसी।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में 30 किलो से अधिक संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है। इन मामलों में छह यात्रियों को पकड़ा गया है। सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, 9 सितंबर को एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे विमान के दो यात्रियों पर निगरानी रखी गई। उनके चेक-इन सामान की निगरानी के दौरान पता चला कि काठमांडू से दिल्ली पहुंचे दो अन्य यात्री उनका सामान लेने का प्रयास कर रहे थे। कस्टम अधिकारियों ने दोनों को ग्रीन चैनल से बाहर निकलते समय पकड़ लिया।

पूछताछ में उन्होंने बताया कि बैंकॉक से आए यात्रियों का सामान लेने के लिए उन्हें कहा गया था। इसके बाद बैंकॉक से आए दोनों यात्रियों को भी रोका गया। उनके सामान की एक्स-रे जांच में संदिग्ध तस्वीरें मिलने पर तलाशी ली गई। सामान से हरे रंग का पदार्थ बरामद हुआ, जो प्रथम दृष्टा हाइड्रोपोनिक गांजा प्रतीत हुआ। पैकेजिंग समेत इसका कुल वजन 27.450 किलो था। चारों यात्रियों, बरामद पदार्थ और सामान को आगे की कार्रवाई के लिए प्रिवेंटिव शिफ्ट-बी को सौंप दिया गया। वहीं, 7 सितंबर को कस्टम अधिकारियों ने प्रोफाइलिंग के आधार पर फुकेत से बैंकॉक होते हुए दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री को टर्मिनल-3 के ग्रीन चैनल पर रोका।

उसके ट्रैवल बैग की जांच में गांजा/मारिजुआना के छह पाउच मिले। इनका शुद्ध वजन 2.8575 किलो था और अनुमानित कीमत 99.99 लाख रुपये बताई गई।

गाजियाबाद में धार्मिक आयोजनों को बड़ी राहत!

दुर्गा-काली-सरस्वती पूजा और गणेश चतुर्थी के लिए पार्क बुकिंग पर 80% छूट।

गाजियाबाद,एजेंसी।

शहर में आगामी दिनों में होने वाले दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा और गणेश चतुर्थी के धार्मिक आयोजनों को लेकर गाजियाबाद नगर निगम ने आयोजकों को बड़ी राहत दी है। महापौर सुनीता दयाल ने धार्मिक आयोजनों के लिए नगर निगम के उद्यान विभाग के अंतर्गत आने वाले पार्कों की बुकिंग में 80 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत लागू होगी।नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न पार्कों और अन्य निर्धारित स्थलों पर प्रत्येक वर्ष दुर्गा, काली, सरस्वती पूजा और गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

धार्मिक आयोजनों को देखते हुए आयोजन समितियों की ओर से लंबे समय से पार्कों की बुकिंग फीस में छूट देने की मांग की जा रही थी। आयोजकों का कहना था कि शुल्क अधिक होने के कारण धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में आर्थिक परेशानी सामने आती है। मामले को लेकर महापौर सुनीता दयाल ने नगर निगम अधिकारियों के साथ वार्ता कर आयोजकों की मांग पर विचार-विमर्श किया।

इसके बाद महापौर की ओर से पत्र जारी कर पूर्व निर्धारित स्थानों पर पार्क आरक्षित करने के लिए सदन की बैठक द्वारा तय बुकिंग दरों में 80 प्रतिशत की छूट देने के निर्देश दिए गए। महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आस्था से जुड़े इन आयोजनों का आयोजन किया जाता है। नगर निगम की ओर से इन स्थलों के लिए शुल्क निर्धारित है और आयोजन समितियों को उसकी रसीद भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि समितियों की ओर से लगातार बुकिंग शुल्क में राहत की मांग की जा रही थी।

महापौर ने बताया कि नगर आयुक्त के साथ हुई वार्ता के बाद आयोजकों को 80 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों को नगर निगम का सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना अनावश्यक आर्थिक दबाव के अपने कार्यक्रमों का आयोजन धूमधाम से कर सकें। नगर निगम प्रशासन के इस फैसले से दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा और गणेश चतुर्थी के आयोजकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। महापौर ने कहा कि नगर निगम धार्मिक आयोजनों को निर्धारित नियमों के अनुसार सुगम और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करेगा।

आरडब्ल्यूएच प्रणाली की 20 दिन में की जाए दोबारा जांच: डी.एस. ढेसी

गुरुग्राम,एजेंसी।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल और समीक्षा बैठकों के बाद हाउसिंग सोसाइटियों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणालियों में सुधार देखा गया है। हरियाणा के शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी ने बृहस्पतिवार को जीएमडीए कार्यालय में इन प्रणालियों के कामकाज और रखरखाव की समीक्षा की। बैठक में हाल की बारिश के दौरान आरडब्ल्यूएच प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन किया गया। जीएमडीए के डीटीपी प्रवर्तन, आर. एस. बत्थ को 20 दिनों के बाद इन सोसाइटियों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया गया।

उन्हें जागरूकता के लिए और सोसायटियों में मॉक ड्रिल आयोजित करने को भी कहा गया। डेवलपर्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस बार बारिश के पानी का प्रबंधन बेहतर रहा और सोसाइटियों में जलभराव नहीं हुआ। कुछ सोसाइटियों ने नई आरडब्ल्यूएच पिट्स भी बनाई हैं, जिससे व्यवस्था में सुधार हुआ है। हालांकि, कुछ नई आरडब्ल्यूएच संरचनाएं लगातार बारिश के बाद ठीक से काम नहीं कर पाईं। संबंधित सोसाइटियों को इन कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

जीएमडीए के इंजीनियरिंग विंग ने सेक्टर-72 स्थित टाटा हाउसिंग परियोजना की आरडब्ल्यूएच प्रणाली को अच्छी स्थिति में पाया। इसके विपरीत, सेक्टर-69 और 70 की ट्यूलिप सोसाइटी में वर्षा जल संचयन व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। सोसाइटी को सुधारात्मक उपाय करने और प्रणाली के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

घर बैठे कमाई का झांसा देकर पौने छह लाख रुपए ठगे

गाजियाबाद,एजेंसी।

घर बैठे ऑनलाइन काम करके रोजाना तीन से पांच हजार रुपये कमाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने प्रताप विहार निवासी युवक से 5.67 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने पहले व्हाट्सऐप पर संपर्क कर ऑनलाइन रेटिंग और रिव्यू का काम देने की बात कही। विश्वास जीतने के लिए डेमो टास्क कराया और उसके बदले 130 रुपये का भुगतान भी किया। इसके बाद पीड़ित को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर अलग-अलग टास्क के नाम पर रकम ट्रांसफर कराई गई।

प्रताप विहार के सेक्टर-11 निवासी प्रशांत ध्यानी ने साइबर थाने में शिकायत देकर बताया कि 31 अगस्त को उनके व्हाट्सऐप पर एक महिला का संदेश आया। उसने अपना नाम अमृता शर्मा बताते हुए खुद को एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की प्रतिनिधि बताया। महिला ने ऑनलाइन रेटिंग और रिव्यू का काम करने पर रोजाना तीन से पांच हजार रुपये कमाने का झांसा दिया। शुरुआत में उन्हें एक डेमो टास्क दिया गया। इसे पूरा करने के बाद उन्हें 130 रुपये का भुगतान भी किया गया।

इससे उन्हें जालसाजों पर भरोसा हो गया। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम आईडी के माध्यम से आगे के टास्क दिए गए। एक अन्य टेलीग्राम उपयोगकर्ता को उनका अध्यापक और मार्गदर्शक बताया गया। उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ा गया, जिसमें उनके अलावा तीन अन्य उपयोगकर्ता मौजूद थे। आरोप है कि ग्रुप में टास्क पूरा कर कम समय में अधिक कमीशन कमाने का लालच दिया गया। इसके बाद एक वेबसाइट का लिंक भेजकर उनका पंजीकरण कराया गया।

पीड़ित के मुताबिक वेबसाइट पर अलग-अलग टास्क के लिए उनसे रकम जमा करने को कहा गया। जालसाजों ने इसे प्रीपेड टास्क और कमीशन टास्क का नाम दिया। प्रत्येक भुगतान के बाद उन्हें अधिक लाभ और कमीशन मिलने का भरोसा दिलाया जाता रहा। शुरुआत में छोटे भुगतान से विश्वास कायम करने के बाद धीरे-धीरे बड़ी रकम ट्रांसफर कराई गई। जब उन्होंने वेबसाइट पर जमा रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने और भुगतान करने के लिए कहा। रकम निकालने के नाम पर लगातार नई शर्तें बताई गईं। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम पर एक कस्टमर सर्विस आईडी भी भेजी गई। कस्टमर सर्विस के नाम पर संपर्क करने वाले व्यक्ति ने भी रकम वापस दिलाने के लिए प्रक्रिया पूरी करने और अतिरिक्त भुगतान करने का दबाव बनाया।

पीड़ित के मुताबिक 31 अगस्त से दो सितंबर के बीच जालसाजों ने उनसे कुल 5.67 लाख रुपये की ठगी की। इसके बाद उन्होंने साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई तथा साइबर थाने में भी प्रार्थना-पत्र दिया।

बंद घरों में चोरी करने वाले दो चोर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

लोनी,एजेंसी।

अंकुर विहार थाना पुलिस ने जांच के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद बंद घरों में चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके कब्जे से क्षेत्र में एक घर से दो दिन पूर्व चोरी किए गए जेवर, दो तमंचे, दो कारतूस और 4700 रुपये बरामद हुए है। पुलिस ने घायल चोरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अंकुर विहार थाना पुलिस बुधवार रात क्षेत्र में वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस को घरों में चोरी करने वाले चोरों की खन्ना नगर कॉलोनी में आने की सूचना मिली।

पुलिस ने सूचना पर बुधवार रात क्षेत्र में जगह जगह वाहनों की जांच शुरू की। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुलिस टीम गढ़ी कटैया मार्ग पर रामलीला मैदान के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक बाइक पर आ रहे दो युवकों को रुकने का इशारा किया। जिस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए।

पूछताछ में घायल बदमाशों ने अपना नाम आकिब निवासी गांव मडौरा थाना सोनीपत हरियाणा मूल पता लिसाड़ी गांव थाना लिसाड़ी गेट मेरठ और ध्यान सिंह निवासी मधुपुर थाना भरथना जिला मैनपुरी बताया। दोनों ने बताया कि सात सितंबर को सुंदर विहार कालोनी स्थित माधव मिश्रा के बंद घर में चोरी की थी। उन्होंने बताया कि दोनों चोरी की घटना को अंजाम देने की नियत से घूम रहे थे। पुलिस को इनके कब्जे से दो तमंचे, दो कारतूस, ताला तोड़ने वाले कटर और अन्य उपकरण, 4700 रुपये और चोरी किए गए जेवर बरामद हुए है।

पूछताछ में इन्होंने दो साथियों के नाम पुलिस को बताए। पुलिस की एक टीम फरार साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार ने बताया कि घायल चोर आकिब के खिलाफ थाना अंकुर विहार में नकबजनी और दिल्ली में लूट का मुकदमा दर्ज है।

RNI.No DLHIN/25/A2841

स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मे. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

दिल्ली में आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य को मिलेगी गतिः रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा,दिल्ली सरकार अब अपनी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का गठन करेगी।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार अब अपनी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का गठन करेगी। इससे आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ बल को घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचाने, राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा जान-माल के नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी।

एसडीआरएफ के गठन के साथ ही दिल्ली सरकार अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को भी विशेष प्रशिक्षण दिलाएगी ताकि आपदा की स्थिति में उपलब्ध स्थानीय मानव संसाधन आवश्यक कौशल और बेहतर समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में योगदान दे सकें। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में एनडीआरएफ अधिकारियों ने दिल्ली में एसडीआरएफ के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि दिल्ली में एसडीआरएफ 1100 जवान के बटालियन का गठन किया जा सकता है। यह बटालियन राज्य सरकार के अधीन कार्य करेगी और उसके आदेश पर आपदा की स्थिति में घटनास्थल पर तेजी से पहुंचकर प्रभावी राहत व बचाव कार्य कर सकेगी। एनडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित एसडीआरएफ के जवानों को आवश्यक प्रशिक्षण एनडीआरएफ उपलब्ध कराएगी।

दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष उपकरण आदि में एनडीआरएफ सहायता करेगी। एसडीआरएफ के गठन के बाद दिल्ली सरकार अपने फायर विभाग के स्टाफ और सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को भी प्रशिक्षण दिलाएगी ताकि आपदा के समय विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ राहत-बचाव कार्य किए जा सकें। सरकार का मानना है कि आपदा के समय राहत और बचाव में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा त्वरित प्रतिक्रिया है। एसडीआरएफ के गठन, फायर विभाग एवं सिविल डिफेंस वॉलंटियरों के प्रशिक्षण से राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे आपदा प्रबंधन से जुड़े उपकरणों की लिस्ट व उनके भंडारण की जानकारी संबंधित विभागों को साझा करें ताकि दुर्घटना या आपदा के समय उन्हें तुरंत उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अपनी एसडीआरएफ का गठन लंबे समय से अपेक्षित था। देश के अधिकतर राज्यों में एसडीआरएफ का गठन हो चुका है।

राजधानी दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले महानगर में एसडीआरएफ का होना समय की जरूरत है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में विभिन्न कारणों से यह महत्वपूर्ण व्यवस्था आकार नहीं ले सकी। दिल्ली सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ेगी ताकि आपदा की स्थिति में बाहरी सहायता पर निर्भरता कम हो और स्थानीय स्तर पर तत्काल प्रतिक्रिया की क्षमता मजबूत हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है और आबादी भी लगातार बढ़ रही है।

ऐसे में प्राकृतिक या मानवीय आपदा की स्थिति में गंभीर क्षति की आशंका को देखते हुए पहले से मजबूत तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र जरूरी है। इसका उद्देश्य आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने के साथ-साथ ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली को पहले से तैयार और सक्षम बनाना है। बैठक में एनडीआरएफ को दिल्ली में अपनी बटालियन रखने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के विषय पर भी चर्चा हुई। एनडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में उनके पास जमीन उपलब्ध है, जहां जवान मुस्तैद रहते हैं।

दिल्ली में 13 से 20 सितंबर तक विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन

नई दिल्ली, साहस समाचार।

दिल्ली में 13 से 20 सितंबर तक 30वां विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सावन कृपाल रूहानी मिशन के प्रमुख संत राजिन्दर सिंह जी महाराज के मार्गदर्शन में होने वाले सम्मेलन में अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा सहित विभिन्न देशों और भारत के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन के कार्यक्रम 13 से 18 सितंबर तक कृपाल बाग तथा 19 और 20 सितंबर को बुराड़ी स्थित संत दर्शन सिंह जी धाम में होंगे। इसमें आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान-अभ्यास की कार्यशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों के भी शामिल होने की संभावना है।

सम्मेलन की शुरुआत संत राजिन्दर सिंह जी महाराज के सत्संग प्रवचन से होगी। 14 सितंबर को संत दर्शन सिंह जी महाराज की 105वीं जयंती के अवसर पर 'दर्शन—अनंत प्रेम और करुणा के सागर' विषय पर सेमिनार आयोजित किया जाएगा।

इस दौरान समाजसेवा से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। आयोजकों के मुताबिक 12 सितंबर को 68वां रक्तदान शिविर, 13 सितंबर को 43वां निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद सर्जरी शिविर और 20 सितंबर को 23वां वस्त्र वितरण शिविर लगाया जाएगा। संत राजिन्दर सिंह जी

महाराज के 80वें जन्मोत्सव के अवसर पर 19 सितंबर को रूहानी कव्वाली का कार्यक्रम होगा। 20 सितंबर को सम्मेलन के समापन सत्र के साथ अन्य मानव-कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राष्ट्र निर्माण में अपनी योगदान दें युवाः विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि भविष्य को लेकर दबाव न लें, प्रयास करते रहे, सीखते रहें, जिज्ञासु बने रहें और राष्ट्र निर्माण में अपनी ओर से हर संभव योगदान दें। गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा का भ्रमण करने आए विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान कहा कि भविष्य को लेकर दबाव न लें। प्रयास करते रहे, सीखते रहें, जिज्ञासु बने रहें और राष्ट्र निर्माण में अपनी ओर से हर संभव योगदान दें।

भारत के भविष्य को आकार देने में प्रत्येक युवा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने छात्रों को उनकी जीवन-यात्रा को लेकर आत्मविश्वास बनाए रखने तथा शैक्षणिक, व्यावसायिक या सामाजिक दबावों को अपनी क्षमताओं पर हावी न होने देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में देश के विकास में योगदान दे सकता है और राष्ट्र निर्माण केवल राजनीति या सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा,आप भविष्य में जो भी पेशा चुनें, उसे ईमानदारी, उत्कृष्टता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ निभायें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती अंततः जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों पर निर्भर करती है। उन्होंने छात्रों को विभिन्न विचारों को सुनने, प्रश्न पूछने तथा किसी विषय पर अपनी राय बनाने से पहले उसे समझने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मतभिन्नता और बहस एक जीवंत लोकतंत्र के स्वाभाविक एवं आवश्यक तत्व हैं, बशर्ते वे संवैधानिक मूल्यों और परस्पर सम्मान की भावना के दायरे में हों।

विद्यार्थियों ने गुप्ता के साथ विधायिका के कामकाज, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका, लोकतांत्रिक भागीदारी तथा नागरिकों और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच संबंधों से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। इस दौरान छात्रों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और समकालीन मुद्दों के साथ-साथ बदलते भारत में युवा नागरिकों की भूमिका पर अपने विचार भी साझा किए।

विधानसभा अध्यक्ष ने छात्रों से भारत की संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक विरासत से जुड़े रहने तथा भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ने का आह्वान किया।

खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत न करने पर सरकार को नोटिस

नई दिल्ली,साहस समाचार।

बुराड़ी क्षेत्र में सीवर-पाइपलाइन के काम के लिए सड़कों की खुदाई के बाद उन्हें ठीक नहीं किए जाने और प्रदूषण बढ़ने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई इलाकों में सड़कें लंबे समय से बदहाल हैं और वाहनों की आवाजाही से लगातार धूल उड़ रही है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की है। मामला बुराड़ी निवासी अधिवक्ता नंदना हरिकृष्णन की ओर से दायर आवेदन से जुड़ा है।

याचिका में कहा गया कि बुराड़ी और आसपास के इलाकों में करीब दो लाख लोग बदहाल सड़कों और धूल की समस्या से प्रभावित हैं। खासतौर पर नत्थूपुरा से आउटर रिंग रोड तक का मार्ग लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है। इस मार्ग पर नालंदा स्कूल और बुराड़ी सरकारी अस्पताल के पास भी सड़कें कई बार खोदी गईं। याचिका के मुताबिक, सीवर और पाइपलाइन का काम वर्ष 2022 से अलग-अलग हिस्सों में चलता रहा, लेकिन खुदाई के बाद सड़कों की पर्याप्त मरम्मत नहीं की गई।

आवेदन में यह भी कहा गया कि धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव नियमित और प्रभावी तरीके से नहीं हो रहा।

डीयू में पांच साल में हॉस्टल में सीटों की संख्या होगी दोगुनी

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि वह अपने यहां हॉस्टल की सीटों में वृद्धि करेगा। कुछ हॉस्टल निर्माणाधीन हैं जो अगले कुल वर्षों में पूरे हो जाएंगे। इससे हास्टल में सीटों की संख्या दो गुनी हो जाएगी। डीयू का कहना है कि विश्वविद्यालय हॉस्टलों को लेकर पिछले वर्षों में काफी गंभीरता से काम करता रहा है, इसी का परिणाम है कि पिछले 4-5 वर्षों में डीयू में हॉस्टलों की सीटों की संख्या दोगुने से अधिक होने जा रही है। आगामी दिनों में भी विश्वविद्यालय द्वारा सरकार के पास जल्दी ही कई नए प्रोजेक्ट्स सबमिट किए जाएंगे। हालांकि डीयू में वर्तमान में 2.75 लाख लगभग छात्र रेगुलर की पढ़ाई में नामांकित हैं।

ऐसे में यह सीटें 10 फीसद भी नहीं हैं। डीयू द्वारा जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि पिछले 100 वर्ष में यूनिवर्सिटी स्तर पर 3422 हॉस्टल सीटें थी। अब इनमें 3922 नई सीटों की वृद्धि के साथ कुल सीटों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 7344 होने जा रही है। विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में भी पिछले 100 वर्षों में कुल उपलब्ध सीटों की संख्या 3788 थी, जिसमें 1622 सीटों की वृद्धि के साथ कॉलेजों में कुल हॉस्टल सीटों की संख्या बढ़कर 5410 होने जा रही है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी दिनों में डीयू और इसके कॉलेजों को मिलकर कुल हॉस्टल क्षमता 12754 सीटों की होने जा रही है। नई सीटों के लिए हॉस्टलों का निर्माण जारी है जिसके आगामी महीनों में पूरा होने का अनुमान है। डीयू के ढाका कॉम्प्लेक्स में ही 1450 सीटों वाले आईओई हॉस्टल का निर्माण चल रहा है जोकि बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। इसके अलावा निर्भया रेजीडेंसल अकोमोडेशन के नाम से महिलाओं के लिए 1000 सीटों का हॉस्टल निर्माणाधीन है।

इसके अतिरिक्त 1050 सीटों वाला स्टूडियो अपार्टमेंट भी निर्माणाधीन है। ऐसे ही और भी हॉस्टलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निकट भविष्य में कई और नए हॉस्टल प्रोजेक्टों पर भी काम शुरू होने जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी प्रिंसिपलों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करें। मौजूदा छात्रावासों के साथ अगर उनके यहां कोई छात्रावास निर्माणाधीन है तो कोशिश करें कि उसे शीघ्रता से पूरा किया जाए और वह जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो।

सभी प्रिंसिपल अपने-अपने कॉलेजों में नए छात्रावासों के निर्माण की भी संभावनाएं तलाशें। अगर संभावनाएं हैं, तो जल्द से जल्द उसके लिए योजना तैयार करें। इसके लिए उपलब्ध स्थान, सरकारी योजनाओं और संभावित सभी आवश्यकताओं व योजनाओं का आकलन करके नए छात्रावास निर्माण का कार्य शुरू करें।

176 नए वाहनों से दक्षिणी दिल्ली की सफाई होगी मजबूत

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली नगर निगम ने दक्षिणी दिल्ली में घर-घर कचरा संग्रहण और उसके परिवहन की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गुरुवार को निगम मुख्यालय स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर से 176 नए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों की तैनाती से दक्षिणी क्षेत्र के पांच वार्डों में कचरा संग्रहण, उठान और परिवहन की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र में 176 नए स्वच्छता वाहनों की तैनाती दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि निगम स्वच्छता संसाधनों में लगातार वृद्धि कर रहा है और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की सफाई व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि नए स्वच्छता वाहनों की तैनाती दक्षिणी क्षेत्र के वसंत विहार, वसंत कुंज, ग्रीन पार्क, ग्रेटर कैलाश और सी.आर. पार्क वार्डों में की जा रही है। इनमें 150 प्राथमिक कचरा संग्रहण वाहन शामिल हैं।

इन वाहनों में 112 टिपर तथा 38 ई-रिक्शा और तिपहिया वाहन हैं। इनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा 26 द्वितीयक वाहन भी स्वच्छता व्यवस्था में लगाए गए हैं। इनमें कचरा संग्रहण वाहन, हुक लोडर, टाटा-407, जेसीबी और बॉबकेट जैसे वाहन शामिल हैं। इन वाहनों का उपयोग कचरे के उठान, परिवहन और प्रबंधन में किया जाएगा। निगम का मानना है कि प्राथमिक और द्वितीयक वाहनों की संख्या बढ़ने से कचरे के संग्रहण से लेकर उसके उचित स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि स्वच्छता और कचरा प्रबंधन निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। दक्षिणी दिल्ली के पांच महत्वपूर्ण वार्डों में आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल स्वच्छता वाहनों की तैनाती से जमीनी स्तर पर सफाई सेवाओं की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में प्राथमिक और द्वितीयक वाहनों की उपलब्धता से कचरा संग्रहण और परिवहन की पूरी व्यवस्था अधिक प्रभावी तथा व्यवस्थित होगी। सत्या शर्मा ने कहा कि निगम का उद्देश्य नागरिकों को नियमित, बेहतर और जवाबदेह स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के साथ-साथ उनके प्रभावी उपयोग और निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि निगम स्वच्छता और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक, कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि सभी नए वाहन विद्युत चालित और पर्यावरण-अनुकूल हैं।

मंत्री आशीष सूद को नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिएः घनेंद्र भारद्वाज

नई दिल्ली,साहस समाचार।

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ने एक बार फिर से दिल्ली की बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर करारा हमला बोला है, श्री घनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार और बीजेपी की एमसीडी के भ्रष्टाचार के चलते दिल्ली के सत्या निकेतन में 7 मासूम और निर्दोष छात्रों की जान चली गई लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री रील बनाने और फ़ोटो शूट में व्यस्त है। घनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि जिस दिन यह दुखद घटना हुई उसी दिन सब जानते हुए भी शिक्षा मंत्री आशीष सूद मौज मस्ती करने गोवा चले गए और जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ASAP उन 7 मासूम बच्चों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा और भजन संध्या का आयोजन कर रही है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद बड़ी बेशर्मी से फोटोशूट और रील बनाने में ही व्यस्त हैं!

घनेंद्र भारद्वाज ने काफी 12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में कोई हॉस्टल नहीं है इसलिए मजबूरी में छात्र-छात्राएं महंगे किराए पर पीजी में रहने पर मजबूर है साउथ कैंपस में सारे पीजी बीजेपी के स्थानीय विधायक अनिल शर्मा और उनके गुर्गे ही चलाते हैं, श्री भारद्वाज ने कहा कि अनिल शर्मा और आशीष सूद पीजी माफिया के बड़े संरक्षक बन चुके हैं और यहां तक की कई पीजी माफिया तो रेखा गुप्ता से भी संबंध होने की बात करते हैं! घनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि अगर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सुख में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि यह पहला हादसा नहीं है दिल्ली में बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार के चलते लगातार ऐसे हादसे होते जा रहे हैं और बीजेपी की सरकार हर हादसे के बाद चुप्पी साध लेती है!

बात मुद्दे की

आलोक गौड़

वोटर सूची से नाम हटाना सिर्फ आंकड़ा नहीं, लोकतंत्र का सवाल है

नई दिल्ली। लोकतंत्र में सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन बहुमत का फैसला मतदाता करता है। इसलिए मतदाता सूची कोई सरकारी कागज नहीं, लोकतंत्र की बुनियादी किताब है। इस किताब से किसी नागरिक का नाम गायब होना महज प्रशासनिक गलती नहीं हो सकती। सवाल सीधा है—जिस नागरिक को वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है, उसका नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी, कितनी विश्वसनीय और कितनी जवाबदेह है? दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने इसी सवाल को खड़ा कर दिया है।

एसआईआर शुरू होने के दौरान जुलाई में करीब 11.9 लाख मतदाताओं को अनुपलब्ध मतदाता' या बाहर रखे जाने योग्य श्रेणी में चिह्नित किए जाने की खबर सामने आई थी। उस समय इसे लेकर सवाल उठे थे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं तक फॉर्म क्यों नहीं पहुंच पाए या उनके फॉर्म क्यों जमा नहीं हो सके। लेकिन अब मामला उस शुरुआती आंकड़े से कहीं आगे निकल चुका है। 1 सितंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में 1.45 करोड़ मतदाताओं में से करीब 47.7 लाख नाम शामिल नहीं हैं। यानी दिल्ली के लगभग हर तीन मतदाताओं में से एक का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है।

चुनाव आयोग का तर्क है कि इन नामों में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे नाम वाले मतदाता शामिल हैं। यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक दावा कर अपना नाम फिर जुड़वा सकते हैं और अंतिम सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी।

यानी आयोग के पास प्रक्रिया का जवाब है। लेकिन लोकतंत्र के पास एक और सवाल है—अगर मतदाता का नाम पहले से मतदाता सूची में था तो उसे हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या एक नागरिक को हर कुछ वर्षों बाद यह साबित करना पड़ेगा कि वह वही व्यक्ति है, उसी देश का नागरिक है और उसे वोट देने का अधिकार है? अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को जानकारी नहीं मिली, कोई किराएदार नौकरी के कारण कुछ दिन बाहर रहा, कोई परिवार शहर के भीतर स्थानांतरित हुआ, किसी घर में बूथ लेवल अधिकारी नहीं पहुंचा या फॉर्म भरने में तकनीकी गलती हुई तो क्या उसका लोकतांत्रिक अधिकार भी अस्थायी रूप से खत्म मान लिया जाए?

सबसे गंभीर बात यह है कि दिल्ली जैसे महानगर में लोगों का आना-जाना सामान्य बात है। किराए के मकान, नौकरी, कारोबार और परिवार की परिस्थितियों के कारण लोग बार-बार घर बदलते हैं। ऐसे में 'अनुपस्थित' या 'स्थानांतरित' होने की पहचान और स्थायी रूप से मताधिकार से बाहर हो जाने के बीच बहुत बड़ा फर्क है। एसआईआर के आंकड़े खुद इस फर्क को गंभीर बनाते हैं। सत्यापन चरण में दिल्ली के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ करीब 97.5 लाख के फॉर्म डिजिटाइज हुए थे। बाकी 47.62 लाख को 'अनुपलब्ध श्रेणी में रखा गया। अब जरा चुनावी राजनीति के आईने में इस आंकड़े को देखिए।

दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में जिन इलाकों में मतदान प्रतिशत कम था, उन्हीं इलाकों में ड्राफ्ट सूची में नाम हटने का प्रतिशत ज्यादा दिखाई देता है। दक्षिण-पूर्वी जिले में 2025 में मतदान प्रतिशत 56.4 था और ड्राफ्ट सूची में हटाए गए नामों का प्रतिशत 43.61 बताया गया। नई दिल्ली में मतदान 57.23 प्रतिशत था और नाम काटने की दर 39.02 प्रतिशत। दक्षिण दिल्ली में मतदान 58.2 प्रतिशत था और नाम हटाने की दर 38.64 प्रतिशत। यह अपने आप में किसी साजिश का प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या यह इतना बड़ा संयोग है कि इसकी स्वतंत्र और सार्वजनिक जांच की जरूरत ही न समझी जाए?

चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव कराना नहीं है। उसका सबसे बड़ा दायित्व चुनाव की विश्वसनीयता बनाए रखना है। मतदाता सूची पर उंगली उठती है तो उसका असर सिर्फ किसी एक पार्टी पर नहीं पड़ता, पूरी चुनाव व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ता है।

राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगना नई बात नहीं। लेकिन इस विवाद में असली सवाल किसी पार्टी का नहीं, मतदाता का है। अगर 47 लाख से अधिक नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं और इनमें से बड़ी संख्या वास्तव में पात्र मतदाताओं की निकलती है तो सवाल होगा कि इतनी बड़ी संख्या को सूची से बाहर करने की प्रक्रिया में क्या कमी रह गई? और अगर इनमें से अधिकांश नाम वास्तव में मृत, स्थानांतरित या दोहरे पाए जाते हैं तो चुनाव आयोग को पूरी जानकारी सार्वजनिक करने में हिचक क्यों होनी चाहिए?

लोकतंत्र में सफाई जरूरी है। मतदाता सूची में फर्जी नाम नहीं होने चाहिए। मृत व्यक्ति के नाम नहीं होने चाहिए। दोहरे नाम नहीं होने चाहिए। लेकिन मतदाता सूची की 'सफाई' के नाम पर एक भी जीवित और पात्र नागरिक का नाम गलती से हटना भी गंभीर गलती है। क्योंकि फर्जी नाम का वोट नहीं पड़ता तो एक फर्जी वोट का नुकसान होता है, लेकिन किसी असली मतदाता का नाम हट गया तो उस नागरिक का वास्तविक वोट ही खत्म हो जाता है।

और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील पक्ष है।

आयोग कह सकता है कि दावा-आपत्ति का रास्ता खुला है। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस नागरिक का नाम पहले से सूची में था, उससे दोबारा अधिकार साबित करने की जिम्मेदारी क्यों पैदा हुई? व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र नागरिक का नाम बिना पर्याप्त सत्यापन के न हटे।

संपादकीय

अधिकारी बदलते हैं, व्यवस्था क्यों नहीं?

देवेंद्र सिंह तोमर

सरकारी दफ्तरों में तबादला कोई नई बात नहीं। अधिकारी आते हैं, कुछ समय काम करते हैं और फिर उनका स्थानांतरण हो जाता है। नई जिम्मेदारी, नया जिला, नया विभाग और नई कार्यशैली प्रशासनिक व्यवस्था इसी तरह आगे बढ़ती है। लेकिन असली सवाल यह है कि अधिकारी बदलने के बाद भी आम आदमी की समस्याएं क्यों नहीं बदलतीं? सड़क वही टूटी रहती है, अस्पताल में वही अव्यवस्था बनी रहती है, थाने में वही शिकायतें लंबित रहती हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए नागरिक को वही चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह सवाल केवल प्रशासनिक फेरबदल का नहीं, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली का है।

हमारे यहां अक्सर यह मान लिया जाता है कि किसी समस्या का समाधान अधिकारी बदलने से हो जाएगा। किसी विभाग में शिकायत बढ़ी तो अधिकारी बदल दिया गया, किसी जिले में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठे तो तबादला कर दिया गया, किसी योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं रही तो जिम्मेदारी बदल दी गई। लेकिन क्या केवल चेहरे बदलने से व्यवस्था बदलती है? अगर व्यवस्था की बुनियादी कमियां जस की तस रहें तो नए अधिकारी से भी कुछ समय बाद वही शिकायतें सामने आनी स्वाभाविक हैं।

तबादला प्रशासन का जरूरी औजार है, लेकिन इसे जवाबदेही का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। किसी अधिकारी का स्थानांतरण यह सुनिश्चित नहीं करता कि उसके कार्यकाल में हुई कमियों की समीक्षा भी होगी। यदि किसी निर्णय में लापरवाही हुई, किसी योजना में अनियमितता हुई या किसी शिकायत को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, तो केवल तबादला पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो सकता। प्रशासन में जवाबदेही का अर्थ यह है कि सही काम के लिए प्रोत्साहन हो और गलत काम के लिए जिम्मेदारी तय हो। दूसरी बड़ी समस्या है लंबे समय तक एक ही व्यवस्था में जड़ जमा लेना। कई बार अधिकारी और कर्मचारी बदलते रहते हैं, लेकिन निचले स्तर की कार्यप्रणाली नहीं बदलती। फाइलें वही गति से चलती हैं, शिकायतों का निपटारा उसी ढर्रे पर होता है और नागरिक को वही पुराने जवाब सुनने पड़ते हैं। इससे साफ है कि समस्या केवल व्यक्ति की नहीं, प्रक्रिया की भी है। प्रशासनिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रक्रियाओं को सरल बनाना होना चाहिए। आम नागरिक को किसी प्रमाणपत्र, अनुमति, पेंशन, राशन, इलाज या पुलिस संबंधी शिकायत के लिए कितने कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं यह किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण पैमाना होना चाहिए। जिस व्यवस्था में नागरिक को अपने अधिकार के लिए बार-बार दरवाजा खटखटाना पड़े, वहां डिजिटल व्यवस्था और जनसुनवाई के दावे अधूरे लगते हैं।

आज सरकारें पारदर्शिता, तकनीक और ऑनलाइन सेवाओं की बात करती हैं। यह जरूरी भी है। लेकिन तकनीक तभी सफल है जब वह नागरिक की परेशानी कम करे। यदि ऑनलाइन आवेदन के बाद भी नागरिक को दस्तावेज लेकर कार्यालय पहुंचना पड़े, यदि शिकायत दर्ज होने के बाद भी उसका समाधान न हो और यदि पोर्टल पर समस्या 'निराकृत' दिखे लेकिन जमीन पर स्थिति वैसी ही हो, तो डिजिटल प्रशासन केवल आंकड़ों की उपलब्धि बनकर रह जाता है।

एक और गंभीर प्रश्न राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप का है। अधिकारी यदि हर निर्णय में यह सोचकर काम करने लगे कि अगला आदेश कब आ सकता है या किसका फोन आ सकता है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रशासन की कल्पना कमजोर पड़ती है। प्रशासनिक अधिकारियों को कानून और नियमों के अनुसार निर्णय लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। साथ ही उस स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। जनता को अधिकारी का नाम नहीं, काम याद रहता है। उसे यह नहीं जानना कि जिले में कलेक्टर कौन है या पुलिस अधीक्षक कौन है; उसे यह जानना है कि उसकी शिकायत का समाधान हुआ या नहीं। किसान को समय पर सुविधा मिली या नहीं, मरीज को अस्पताल में इलाज मिला या नहीं, विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिली या नहीं और पीड़ित को पुलिस से न्याय मिला या नहीं यही शासन की असली परीक्षा है।

भाषाई पुनर्गठन: विविधता को स्वीकार कर मजबूत हुई भारतीय एकता

डॉ. सत्यवान सौरभ

भाषाई पुनर्गठन भारत के राष्ट्र-निर्माण की एक विशिष्ट उपलब्धि है। इसने यह महत्वपूर्ण सबक दिया कि विविधता को दबाकर एकता कायम नहीं की जा सकती। भारत ने अपनी भाषाई विविधता को संवैधानिक ढाँचे में स्थान देकर यह सिद्ध किया कि एकता समानता थोपने से नहीं, बल्कि विविधताओं को सम्मानपूर्वक समायोजित करने से मजबूत होती है।

1948 में गठित धार आयोग ने तत्काल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा नहीं की। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की सदस्यता वाली जेवीपी समिति ने भी 1949 में राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक स्थिरता और नवगठित राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

स्वतंत्रता के समय भारत के सामने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थायी बनाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण भी करना था जिसमें भाषा, संस्कृति, परंपरा और क्षेत्रीय पहचान की असाधारण विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकता कायम रहे। ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली प्रांतीय सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा और औपनिवेशिक हितों के अनुरूप थीं। इनमें अनेक क्षेत्रों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वाभाविक रूप से उठी।

हालाँकि शुरुआती दौर में राष्ट्रीय नेतृत्व भाषाई राज्यों को लेकर आशंकित था। विभाजन की त्रासदी अभी ताजा थी और यह भय था कि यदि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया तो क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो सकती है। किंतु भारतीय लोकतंत्र की विशेषता यही रही कि उसने इन आकांक्षाओं को दबाने के बजाय संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से समायोजित करने का रास्ता चुना। समय ने सिद्ध किया कि भाषाई पहचान को सम्मान देना भारत की एकता के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसकी मजबूती का आधार बन सकता है। भाषाई पहचान की राजनीतिक स्वीकार्यता स्वतंत्रता से पहले ही दिखाई देने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रांतीय संगठनों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया था। इसका उद्देश्य यह था कि जनता से संवाद उनकी भाषा और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में बेहतर ढंग से हो सके। लेकिन स्वतंत्रता और विभाजन के बाद परिस्थितियाँ बदल गईं। राष्ट्रीय नेतृत्व तत्काल किसी बड़े क्षेत्रीय पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था।

1948 में गठित धार आयोग ने तत्काल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा नहीं की। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की सदस्यता वाली जेवीपी समिति ने भी 1949 में राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक स्थिरता और नवगठित राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उस समय यह सावधानी समझ में आती थी, क्योंकि देश राजनीतिक संक्रमण और सामाजिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था।

लेकिन जन आकांक्षाओं को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता था। आंध्र क्षेत्र में तेलुगु भाषी जनता के लिए अलग राज्य की मांग तेज होती गई। पोट्टि श्रीरामुलु के 1952 के आमरण अनशन और उनकी मृत्यु ने इस आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया। व्यापक जनदबाव के बाद 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। यह घटना केवल एक राज्य के निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को गति दी।

इसके बाद सरकार ने समस्या का व्यापक और संस्थागत समाधान खोजने का प्रयास किया। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी अध्यक्षता फज़ल अली ने की, ने भाषाई और सांस्कृतिक आकांक्षाओं के साथ-साथ प्रशासनिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवहार्यता पर भी विचार किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम तथा संविधान का सातवाँ संशोधन लागू हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारत के प्रशासनिक मानचित्र में व्यापक बदलाव आया और 14 राज्यों तथा छह केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था अस्तित्व में आई। भाषाई राज्यों का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय पहचान के बीच टकराव को कम किया। जब किसी समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक पहचान मिली तो अलगाव की भावना कमजोर हुई। लोगों को यह विश्वास मिला कि भारतीय संघ उनकी विशिष्ट पहचान को समाप्त करने के बजाय उसका सम्मान करता है। भाषाई पुनर्गठन का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ प्रशासनिक स्तर पर दिखाई दिया। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शासन-प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता ने राज्य और नागरिक के बीच दूरी कम की। लोकतंत्र तभी प्रभावी होता है जब नागरिक शासन की भाषा और प्रक्रिया को समझ सके। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशासन ने सामान्य नागरिकों की भागीदारी को अधिक सहज बनाया।

इस व्यवस्था ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को भी व्यापक बनाया। स्थानीय भाषा बोलने वाले राजनीतिक नेतृत्व को राज्य स्तर पर उभरने का अवसर मिला। इससे राजनीति अधिक जनसरोकारों से जुड़ी और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएँ राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनीं। भाषाई राज्यों ने यह भी सिद्ध किया कि संघीय व्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रीय पहचानें राष्ट्रीय एकता के साथ सह-अस्तित्व रख सकती हैं।

भारत का पुनर्गठन 1956 पर समाप्त नहीं हुआ। बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में आगे भी परिवर्तन हुए। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन तथा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के साथ हरियाणा का निर्माण इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि भारतीय संघ कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय प्रशासनिक ढाँचा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने वाली व्यवस्था है। हालाँकि भाषाई राज्यों की सफलता का अर्थ यह नहीं कि भाषाई अस्मिता से जुड़ी सभी चुनौतियाँ समाप्त हो गईं। भाषाई बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक भाषाओं की उपेक्षा और क्षेत्रीय श्रेष्ठताबोध जैसी प्रवृत्तियाँ संघीय सद्भाव के लिए चुनौती बन सकती हैं। इसलिए भाषाई पहचान के संरक्षण के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक और लोकतांत्रिक माध्यमों से सुना जाए। किसी भी क्षेत्र की पहचान को राष्ट्र-विरोधी मानना उतना ही अनुचित है जितना क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखना। सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन ही भारतीय संघवाद की वास्तविक शक्ति है।

भाषाई पुनर्गठन भारत के राष्ट्र-निर्माण की एक विशिष्ट उपलब्धि है। इसने यह महत्वपूर्ण सबक दिया कि विविधता को दबाकर एकता कायम नहीं की जा सकती। भारत ने अपनी भाषाई विविधता को संवैधानिक ढाँचे में स्थान देकर यह सिद्ध किया कि एकता समानता थोपने से नहीं, बल्कि विविधताओं को सम्मानपूर्वक समायोजित करने से मजबूत होती है। यही लचीला संघवाद आज भी भारत की लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण आधारशिला है।

जल बचाने की मुहिम में जनभागीदारी जरूरी

डॉ. प्रियंका सौरभ

जल संचय जन भागीदारी की असली सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि कितनी संरचनाएं बनाई गईं। सफलता तब होगी जब तालाबों में पानी लौटे, भूजल स्तर सुधरे, किसानों की पानी पर निर्भरता कम हो और आम लोग पानी बचाने को अपनी जिम्मेदारी समझें। भारत में जल सुरक्षा केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है। सरकार दिशा और संसाधन दे सकती है, लेकिन पानी बचाने की आदत समाज को खुद विकसित करनी होगी।

भारत में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है, तालाब और कुएं सूख रहे हैं तथा खेती और पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ रही है। ऐसे समय में पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती। इसमें आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। इसी सोच के साथ 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान शुरू किया गया है।

6 सितंबर 2024 को शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को बचाना, भूजल स्तर बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर पानी के स्रोतों को मजबूत करना है। इसके तहत कम खर्च में जल संरक्षण की संरचनाएं बनाने, पुराने और बंद पड़े नलकूपों को फिर से उपयोगी बनाने तथा स्थानीय जरूरत के अनुसार जल संरक्षण के उपाय करने पर जोर दिया जा रहा है।

इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें सरकार के साथ आम जनता, पंचायतें, सामाजिक संगठन और कंपनियां भी जुड़ सकती हैं। इसका आधार तीन 'सी' हैं- समुदाय, कंपनियों का सामाजिक दायित्व और लागत। यानी समुदाय की भागीदारी, कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी और कम खर्च में जल संरक्षण। इससे जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना न बनाकर जन-अभियान बनाने की कोशिश की जा रही है।

इस दिशा में बड़ी संख्या में जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई हैं। पहले चरण के तहत मई 2025 तक देश में 27 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गईं। इसके बाद जून 2025 में दूसरा चरण शुरू किया गया। मई 2026 तक डेढ़ करोड़ से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई जा चुकी थीं। 3 सितंबर 2026 तक यह संख्या एक करोड़ 58 लाख से अधिक हो गई। यह आंकड़ा बताता है कि देश में जल संरक्षण को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

केवल संरचनाएं बना देना काफी नहीं है। उनका सही स्थान पर बनना, नियमित रखरखाव और सही उपयोग भी जरूरी है। यदि बारिश का पानी इन संरचनाओं तक पहुंचे ही नहीं या कुछ वर्षों बाद वे मिट्टी और कचरे से भर जाएं तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए स्थानीय लोगों को इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेनी होगी।

भारत में पानी बचाने की परंपरा पहले से रही है। गांवों में तालाब, कुएं, बावड़ियां, जोहड़ और छोटे बांध लोगों की जरूरत पूरी करते थे। हरियाणा और राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में आज भी पुराने जल स्रोत इसकी याद दिलाते हैं। आधुनिक विकास के दौरान हमने इन स्रोतों की उपेक्षा की और भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब समय है कि पुरानी समझ को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाए।

इसी उद्देश्य से जल संचय जन भागीदारी को 'वर्षा जल संचयन' अभियान से भी जोड़ा गया है। जून 2026 में इसे 'जल शक्ति अभियान—वर्षा जल संचयन' के साथ मिलाकर नया रूप दिया गया। इसका सीधा संदेश है- बारिश की हर बूंद को व्यर्थ बहने से रोकना और उसे जमीन में पहुंचाना।

जल संकट का एक बड़ा कारण खेती में पानी का अधिक इस्तेमाल भी है। कई किसान ऐसी फसलें उगाते हैं जिनमें बहुत अधिक पानी लगता है। भूजल निकालने के लिए लगातार नलकूप चलाए जाते हैं। इससे जमीन के नीचे का पानी तेजी से कम होता है। इसलिए पानी बचाने के लिए फसल विविधता, बूंद-बूंद सिंचाई, फुहार सिंचाई और कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना जरूरी है।

जल संरक्षण में ग्राम पंचायतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। हर गांव अपना 'जल बजट' तैयार कर सकता है। इसमें यह देखा जाए कि गांव में सालभर में कितना पानी आता है, कितना पानी खेती और घरों में खर्च होता है और कितना पानी जमीन में वापस पहुंचाया जा सकता है। इससे लोगों को अपने क्षेत्र में पानी की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी।

विद्यालय और महाविद्यालय भी इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों को केवल किताबों में जल संरक्षण पढ़ाने के बजाय विद्यालय परिसर में वर्षाजल संचयन, पौधारोपण और पानी की बचत की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों के माध्यम से पानी बचाने का संदेश घरों तक भी पहुंच सकता है।

1 और 2 सितंबर 2026 को हुए जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन में भी केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। जल संरक्षण के साथ जल जागरूकता, प्रशिक्षण, राज्यों के बीच अनुभव साझा करने और पानी से जुड़े सही आंकड़े तैयार करने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। यह जरूरी है, क्योंकि पानी की समस्या हर राज्य और हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं है। कहीं बाढ़ की समस्या है तो कहीं सूखे की।

जल संरक्षण को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि लोगों की सोच बदले। नल खुला छोड़ना, बारिश के पानी को नालियों में बहने देना, तालाबों पर कब्जा करना और भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना बंद करना होगा। पानी को असीमित संसाधन मानने की सोच बदलनी होगी।

जल संचय जन भागीदारी की असली सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि कितनी संरचनाएं बनाई गईं। सफलता तब होगी जब तालाबों में पानी लौटे, भूजल स्तर सुधरे, किसानों की पानी पर निर्भरता कम हो और आम लोग पानी बचाने को अपनी जिम्मेदारी समझें। भारत में जल सुरक्षा केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है। सरकार दिशा और संसाधन दे सकती है, लेकिन पानी बचाने की आदत समाज को खुद विकसित करनी होगी। हर बूंद बचाना, हर जल स्रोत को बचाना और हर व्यक्ति को जल संरक्षण से जोड़ना ही भविष्य के सुरक्षित भारत की जरूरत है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

जर्मनी में कट्टरपंथी एएफडी की छोटी जीत के बड़े मायने

आजकल जर्मनी में अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड (एएफडी) की एक छोटी-सी जीत की बड़ी चर्चा हो रही है। एएफडी की छोटी-सी जीत से पूरे यूरोप और खासकर इस्लामी जगत में बेचैनी नजर आ रही है। यह जर्मनी की एक ऐसी धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है, जिसने हाल के वर्षों में जर्मन राजनीति में भूचाल ला दिया है। 2013 में स्थापित हुई इस पार्टी ने प्रवासियों के विरोध, यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रति अविश्वास और जर्मन राष्ट्रवाद के दम पर देश के चुनावी परिदृश्य को बदलकर रख दिया है। अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड की स्थापना 6 फरवरी 2013 को हुई थी। शुरुआत में, इस पार्टी का गठन अर्थशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया था, जो मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र के आर्थिक सहायता पैकेज के खिलाफ थे। हालांकि, 2015 के यूरोपीय शरणार्थी संकट के दौरान पार्टी की विचारधारा में एक बड़ा बदलाव आया। पार्टी ने अपना रुख पूरी तरह से धुर दक्षिणपंथी और लोकलुभावन बना लिया। इस विचारधारा के तहत पार्टी का सबसे प्रमुख एजेंडा देश में शरणार्थियों और प्रवासियों के आने पर पूर्ण विराम लगाना है। पार्टी अवैध शरणार्थियों को तेजी से निर्वासित करने की वकालत करती है। उनका मानना है कि प्रवासियों के आने से जर्मनी की पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। वे स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने जैसी नीतियों को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही पार्टी खुले तौर पर जर्मनी में बढ़ते इस्लामीकरण और बहुसंस्कृतिवाद का विरोध करती है। जर्मनी की खुफिया एजेंसी की रिपोर्टों के अनुसार, इसके नेताओं द्वारा कई बार जनविरोधी और नस्लवादी बयान दिए गए हैं। पार्टी यूरोपीय संघ की मौजूदा व्यवस्था में बड़े बदलाव या उससे पूरी तरह बाहर निकलने की बात भी करती है।

धार्मिक रुख की बात करें तो आधिकारिक तौर पर एएफडी स्वयं को ईसाई-यहूदी संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता का रक्षक मानती है। पार्टी का राजनीतिक दर्शन पारंपरिक यूरोपीय ईसाई मूल्यों पर आधारित है। पार्टी पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं, जैसे एक पुरुष और एक महिला का विवाह, और रूढ़िवादी ईसाई सामाजिक मूल्यों का पुरजोर समर्थन करती है। वे प्रगतिशील या आधुनिक उदारवादी विचारों, जैसे स्कूलों में इंद्रधनुषी झंडे लगाने, का विरोध करते हैं। इसके विपरीत, पार्टी का रुख इस्लाम के प्रति बेहद सख्त है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस्लाम जर्मनी का हिस्सा नहीं है और वे मस्जिदों के मीनारों तथा अजान के सार्वजनिक लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते रहे हैं। हालांकि पार्टी ईसाई धर्म की रक्षक बनती है, लेकिन जर्मनी के मुख्यधारा के चर्च, जिनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों शामिल हैं, अक्सर एएफडी की नस्लवादी और विभाजनकारी नीतियों की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं। इसके बावजूद, देश के पारंपरिक ईसाई और रूढ़िवादी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इस पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ है।जर्मनी की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के विपरीत एएफडी में कोई एक अकेला सर्वोच्च नेता नहीं है। यह पार्टी सह-नेतृत्व के मॉडल पर चलती है। वर्तमान में ऐलिस विडेल पार्टी की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली चेहरा हैं। वे संसद में पार्टी की संसदीय समूह की नेता और राष्ट्रीय सह-अध्यक्ष हैं। एक पूर्व निवेश बैंकर होने के नाते, वे पार्टी को एक आधुनिक और आर्थिक रूप से सक्षम छवि देने का प्रयास करती हैं। उनके साथ टिनो क्रुपाल्ला पार्टी के राष्ट्रीय सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्रुपाल्ला मुख्य रूप से पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और पूर्वी जर्मनी के कामकाजी वर्ग के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। प्रांतीय स्तर पर उलरिच सीगमंड का नाम बेहद तेजी से उभरा है, जिन्होंने सैक्सनी-अनहाल्ट के चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इन नेताओं के अलावा ब्योर्न होके थुरिंगिया राज्य में एएफडी के नेता हैं। इन्हें पार्टी के भीतर सबसे कट्टरपंथी और विवादित धड़े का जनक माना जाता है, और जर्मन खुफिया एजेंसियां इन्हें आधिकारिक तौर पर एक दक्षिणपंथी चरमपंथी मानती हैं। जर्मनी के संघवाद में 16 राज्य हैं, और एएफडी की विस्तारवादी नीति देश के भीतर बेहद आक्रामक रही है। भूतपूर्व पूर्वी जर्मनी के राज्यों जैसे सैक्सनी-अनहाल्ट, थुरिंगिया, सैक्सनी और ब्रांडेनबर्ग में एएफडी इस समय सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह राजधानी दिल्ली में ही होना चाहिए : सुप्रिया सुले

मुंबई, एजेंसी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नयी दिल्ली में ही आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि यह देश की राजधानी है। सुले का यह बयान सरकार द्वारा इस साल समारोह को गुजरात स्थानांतरित करने के फैसले के बाद आया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली और मुंबई के महत्व को कम करने का प्रयास हो सकता है क्योंकि क्रिकेट विश्व कप के मैचों और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की यात्राओं समेत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन अब गुजरात में किया जा रहा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह इस बार दिल्ली से बाहर गुजरात के केवड़िया में आयोजित होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को पुरस्कार प्रदान करेंगी। केवड़िया का नाम बदलकर अब एकता नगर कर दिया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का स्थल है। 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के नाम से विख्यात यह प्रतिमा 597 फुट ऊंची है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में किया था। सुले ने यहां संवाददाताओं से कहा, देश के 72 साल के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार गुजरात में आयोजित हो रहे हैं।

युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें : नितिन नवीन

हल्द्वानी, एजेंसी।

उत्तराखंड के लिए पलायन को एक गंभीर चुनौती बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को युवाओं से कहा कि वे केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनने की दिशा में आगे बढ़ें।

अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन नवीन ने यहां युवाओं से संवाद किया और उत्तराखंड के विकास तथा भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की।

नवीन ने युवाओं से अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और कौशल का सकारात्मक उपयोग करते हुए राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सामने पलायन एक गंभीर चुनौती है तथा रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में युवाओं का राज्य से बाहर जाना चिंता का विषय है।भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पलायन रोकने के लिए केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करना होगा।

उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार को बढ़ावा देना जरूरी है।

नवीन ने कहा कि युवा केवल नौकरी पाने की सोच तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी क्षमता और कौशल के आधार पर रोजगार देने वाले बनने की दिशा में भी आगे बढ़ें।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता के माध्यम से युवा न केवल अपने लिए अवसर पैदा कर सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।

नवीन ने कहा कि किसी भी प्रदेश की प्रगति में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उत्तराखंड का भविष्य यहां के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार से तय होगा।

उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों को नीतियों तथा विकास योजनाओं से जोड़ना जरूरी है, ताकि प्रदेश में उनके लिए बेहतर अवसर तैयार किए जा सकें।

संवाद के दौरान युवाओं ने उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करने तथा पलायन की समस्या के समाधान को लेकर नवीन से सवाल पूछे।

उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके जमीनी स्तर पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। युवाओं ने सरकार की योजनाओं में सुधार और उन्हें जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में सुझाव दिए।

इससे पहले, नवीन लालकुआं क्षेत्र के हल्दूचौड़ में अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले बूथ अध्यक्ष राकेश आर्य के घर पहुंचे और उनकी बुजुर्ग माता से आशीर्वाद लिया। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं के सम्मान और उनकी भूमिका को सर्वोच्च महत्व देता है।

उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की मेहनत, निष्ठा और समर्पण से मजबूत होता है।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दूसरे दिन की शुरुआत से पहले नवीन ने सुबह महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और देश तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद अनिल बलूनी, अजय भट्ट समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए मुंबई मार्च जरूर होगा : जरांगे

जालना, एजेंसी।

मराठा आरक्षण आंदोलन के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा है कि उनका प्रस्तावित मुंबई मार्च निश्चित रूप से होगा और 12 सितंबर को समर्थकों के मौजूदा धरना स्थल पर एकत्र होने के बाद मुंबई कूच की तारीख घोषित की जाएगी।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे जरांगे का अनशन बृहस्पतिवार को 13वें दिन भी जारी है। जरांगे ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधिमंडल के धरना स्थल पर आने का इंतजार नहीं है। महाराष्ट्र के जालना जिले के अंतरवाली सराटी में पत्रकारों से बातचीत में जरांगे ने कहा, मैं निश्चित रूप से मुंबई जा रहा हूं। 12 सितंबर को जब हम इकट्ठा होंगे, उसके बाद तारीख घोषित करेंगे।

जरांगे मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वह हैदराबाद और सातारा गजट अभिलेखों को लागू करने तथा पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी (ओबीसी) जाति प्रमाणपत्र जारी करने की मांग भी कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जरांगे ने कहा कि वह यह देखेंगे कि कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शिविर किस तरह आयोजित किए जा रहे हैं और क्या ये शिविर मौजूदा आंदोलन के कारण लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, हमें परिस्थिति के अनुसार काम करना होगा। देखते हैं कि कुनबी प्रमाणपत्र के लिए शिविर किस तरह आयोजित किए जाते हैं।

बुधवार को जरांगे ने राज्य के मंत्री और मराठा आरक्षण उप-समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल पर केवल मीठी बातें करने और आश्वासन देकर समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर 12 सितंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन मुंबई पहुंचेगा।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट पर निशाना साधते हुए जरांगे ने कहा कि शिरसाट की वजह से शिंदे के साथ उनके संबंध खराब हुए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, मैं तीन साल तक एकनाथ शिंदे के बारे में सम्मानपूर्वक बोलता रहा। लेकिन अब वह समुदाय के पक्ष में नहीं, बल्कि एक पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं। जरांगे ने कहा कि वह मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों की ओर से की गई गलतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।

वंदे मातरम पर उमर बधाई के हकदार: ज्योति

लखनऊ,एजेंसी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की चेयरपर्सन साध्वी निरंजन ज्योति ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एआई से तैयार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वीडियो, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की आपत्ति, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' और गरबा आयोजनों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध विचारधारा और विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन या धार्मिक पहचान को निशाना बनाना उचित नहीं है।

कर्नाटक सरकार ने सौ दिन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की : विजयेंद्र

बल्लारी, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को विज्ञापन वाली सरकार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि शिवकुमार सरकार अपने शुरुआती 100 दिन में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी।

विजयेंद्र ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

इससे पहले, शिवकुमार ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर कई नयी पहल की शुरुआत की थी। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर सिद्धरमैया के 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शिवकुमार ने तीन जून को कार्यभार संभाला था।

विजयेंद्र ने एक सवाल के जवाब में कहा, यह सरकार जल्द ही सत्ता से बाहर हो जाएगी। जनता ने पहले ही मन बना लिया है। यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

सार समाचार

लंबित डीए बकाया को लेकर बलबीर सिद्धू का आप सरकार पर हमला

मोहाली,एजेंसी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधा है। सिद्धू ने गुरुवार को कहा कि करीब 6.5 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने जायज डीए बकाये की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई वर्षों से भुगतान लंबित रहने से सरकार पर हजारों करोड़ रुपये की देनदारी बन गयी है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार कर्मचारियों को उनके हक के लिए धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर क्यों कर रही है और बकाया भुगतान की तारीख स्पष्ट रूप से क्यों नहीं घोषित करती।

जम्मू एनसीबी की हिरासत से फरार ड्रग तस्कर जालंधर में गिरफ्तार

जम्मू,एजेंसी। जम्मू स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत से फरार हुआ एक ड्रग तस्कर पड़ोसी राज्य पंजाब के जालंधर में पकड़ा गया है। एनसीबी ने गुरुवार को यहां जारी एक बयान में बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ करीबी समन्वय में एनसीबी ने पुलवामा जिले के काकापोरा निवासी और कुख्यात ड्रग तस्कर आकिब बशीर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया।

वह जम्मू में एनसीबी की हिरासत से फरार हो गया था। अधिकारियों ने कहा, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में तीन दिनों तक लगातार तलाशी और निगरानी अभियान चलाया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस और एनसीबी के बीच त्वरित समन्वय एवं खुफिया जानकारी साझा करने तथा केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली। अधिकारियों के अनुसार जम्मू से फरार होने के बाद आरोपी पठानकोट के रास्ते जालंधर पहुंचा। फरार होने के बाद शुरुआत में उसने अंधेरे का फायदा उठाते हुए जांच एजेंसियों से बचने की कोशिश की और जम्मू में नरवाल फल मंडी के पास जंगल में छिप गया। उन्होंने बताया कि पहचान छिपाने के लिए उसने दाढ़ी-मूंछ पूरी तरह साफ कर ली, कपड़े बदले और अपना हुलिया बदल लिया।

जिलाधिकारी 15-20 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखें : नायडू

अमरावती, एजेंसी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जो देश में सबसे अधिक है।

उन्होंने जिलाधिकारियों से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखने को कहा।

सचिवालय में जिलाधिकारियों के आठवें सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारियों में नेतृत्व क्षमता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

नायडू ने कहा, ''राज्य ने पहली तिमाही में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की, जो भारत में सबसे अधिक है... 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की जानी चाहिए।''

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिलाधिकारियों को नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण देने की रणनीति तैयार कर रही है। दक्षिणी राज्य में कम बारिश के संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और लोगों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने को जिलाधिकारियों को बेहतर योजना के साथ काम करना चाहिए।

कांग्रेस 2028 में कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखेगी: प्रियांक

बेंगलुरु,एजेंसी। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बरकरार रखेगी। खरगे ने कहा कि मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के कार्यकाल के पहले 100 दिन केवल शुरुआत हैं और सरकार राज्य में दीर्घकालिक नीतिगत, आर्थिक तथा रोजगार संबंधी पहल को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है।शिवकुमार पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए राज्य के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार कर रहे हैं। उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। नीतिगत, आर्थिक और रोजगार के क्षेत्र में तेजी लायी जायेगी।

कर्नाटक की शिवकुमार सरकार चुनावी वादे पूरे करे : सिद्धरमैया

बेंगलुरु, एजेंसी।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को डी. के. शिवकुमार नीत सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने, पांच गारंटी योजनाओं को जारी रखने और सूखे की स्थिति से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि इस अवसर को केवल जश्न के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह आकलन करने का मौका होना चाहिए कि सरकार जनता से किए गए अपने वादों को पूरा कर रही है या नहीं।

उन्होंने कहा, ये दिन केवल जश्न मनाने के लिए नहीं हैं। ये हमारे लिए यह देखने का अवसर और जिम्मेदारी है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं।

सिद्धरमैया ने कहा कि विपक्ष के इस आरोप के बावजूद कि पांच गारंटी योजनाओं (गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति और युवा निधि) से राज्य दिवालिया हो जाएगा और विकास कार्यों के लिए धन नहीं बचेगा, इन्हें लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं पर हर साल करीब 52,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गारंटी योजनाओं से सभी समुदायों के गरीब लोगों को लाभ मिला है और दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र के कई अन्य वादों को पूरा किया है तथा विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना जारी रखा है।

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कांग्रेस को भारत को बदलने और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली ताकत बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी 2028 के विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल करेगी।

शिवकुमार ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास आधारित भविष्य की दिशा में काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक के सात करोड़ लोगों की सरकार है।

उन्होंने कल्याण, रोजगार, सिंचाई, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, निवेश और क्षेत्रीय विकास को शामिल करते हुए सरकार का व्यापक दृष्टिकोण पेश किया।

जानवी की मौत के बाद कार्रवाई से हड़कंप

अमरकांत सिंह चौहान

- जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने एनएचएम डायरेक्टर को भेजा कार्रवाई का प्रस्ताव, डॉ. विनीत गुप्ता समेत चार नर्सिंग ऑफिसरों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश।

भिंड, साहस समाचार। जिला अस्पताल में 17 वर्षीय किशोरी जानवी की इलाज के दौरान मौत के मामले में प्रशासनिक जांच के बाद हुई कार्रवाई ने अस्पताल की मरीज निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच का सबसे अहम बिंदु यह सामने आया कि अस्पताल में भर्ती किशोरी आखिर निजी क्लिनिक तक कैसे पहुंची और उसे अस्पताल से बाहर ले जाने की जानकारी ड्यूटी स्टाफ तथा अस्पताल प्रशासन को कब हुई।

कलेक्टर किरोड़ी लाल मीना द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. विनीत गुप्ता समेत चार नर्सिंग ऑफिसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के डायरेक्टर, भोपाल को भेजा गया है। वहीं जांच में जिम्मेदारी सामने आने के बाद दो रेजिडेंट स्टाफ नर्सों को निलंबित किया गया है।

जांच में सामने आया कि जानवी जिला अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसे अस्पताल से बाहर ले जाकर निजी क्लिनिक में मेडिकल जांच कराई गई। मरीज को अस्पताल से बाहर ले जाने से रोकने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी को लेकर नर्सिंग स्टाफ की भूमिका पर सवाल उठे हैं। इसी आधार पर चार नर्सिंग ऑफिसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भर्ती मरीज को निजी क्लिनिक तक ले जाने की अनुमति किस स्तर से मिली। क्या अस्पताल में भर्ती मरीज को बाहर ले जाने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया थी? यदि थी तो उसका पालन हुआ या नहीं? ड्यूटी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को इसकी जानकारी कब हुई और अस्पताल प्रशासन को पूरे घटनाक्रम की सूचना क्यों नहीं मिली? जांच के बाद इन सवालों ने अस्पताल की निगरानी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

ममता बनर्जी की हुगली रैली को दी मंजूरी

कोलकाता,एजेंसी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को 11 सितंबर 2026 को हुगली के श्रीरामपुर (महेश) में राजनीतिक सभा करने की अनुमति दे दी है लेकिन जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कालीघाट तृणमूल कांग्रेस को महेश में जगन्नाथ देव स्नानपिरी मैदान में सभा करने की सशर्त अनुमति दी। अदालत ने निर्देश दिया कि राजनीतिक सभा दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच आयोजित की जाए और सभा में लोगों की संख्या 2,000 से अधिक नहीं हो।

मायावती ने आकाश आनंद को बसपा से पूरी तरह मुक्त किया

लखनऊ, एजेंसी।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने गुरुवार को अपने भतीजे और पूर्व राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह से मुक्त करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के फैसले को 'अति-देर से उठाया गया सही कदम' बताया है। सुश्री मायावती ने गुरुवार को एक्स पर 10 बिंदुओं में विस्तृत पोस्ट कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा कि अशोक सिद्धार्थ अगर यह फैसला काफी पहले ले लेते तो बसपा, बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंट और उनके दामाद आकाश आनंद को लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता और न ही उन्हें विधानसभा आम चुनाव व खासकर यूपी में पांचवीं बार सरकार बनाने की तैयारियों के बीच कड़े फैसले लेने पड़ते।

बसपा प्रमुख ने कहा कि बसपा की अंबेडकरवादी राजनीति की परम्परा त्याग, तपस्या, संघर्ष और निजी-पारिवारिक स्वार्थ से दूर रहने की रही है, जिसे कांशीराम जी की तरह वह भी समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि महान लक्ष्य के लिए बड़ी कुर्बानी की जरूरत होती है।

भाजपा की नाकामी का ठीकरा अधिकारी पर फोड़ रहे बाबूलाल: ऋषीकेश सिंह

रांची, एजेंसी।

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव सह प्रदेश प्रवक्ता ऋषीकेश सिंह ने नगर आयुक्त पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद अधिकारियों को नसीहत देनी चाहिए।

रांची नगर निगम में मेयर भाजपा का, डिप्टी मेयर भाजपा का और नगर निगम पर वर्षों से भाजपा का प्रभाव, रांची विधानसभा में करीब 30 वर्षों से भाजपा का विधायक और रांची लोकसभा में 12 वर्षों से भाजपा का सांसद है। इसके बावजूद रांची की समस्याओं के लिए सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप करना भाजपा नेताओं की पुरानी आदत बन चुकी है। सिंह ने कहा कि यदि नगर निगम की व्यवस्था इतनी ही खराब है, तो बाबूलाल मरांडी अपने ही दल के मेयर, डिप्टी मेयर और निगम में प्रभाव रखने वाले भाजपा नेताओं से जवाब क्यों नहीं मांगते? तीन दशक से रांची की राजनीति पर कब्जा जमाए भाजपा नेताओं ने शहर को क्या दिया, इसका हिसाब जनता मांग रही है। सड़क, नाली, ट्रैफिक, जलजमाव, कचरा, पार्किंग और शहरी व्यवस्था की बदहाली पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने के बजाय अधिकारी को कठघरे में खड़ा करना सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है।

श्री सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं की हालत यह हो गई है कि जहां सत्ता में हैं वहां श्रेय भाजपा का और जहां जनता सवाल पूछे वहां जिम्मेदारी अधिकारी या राज्य सरकार की!

कहा, जिन लोगों को सरकारी नौकरियों की इन शर्तों से काफी परेशानी है, वे नौकरी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं

राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन करने वालों का सख्त इलाज करने की जरूरत है: शुभेंदु

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यादवपुर विश्वविद्यालय के वामपंथी रुझान वाले शिक्षकों और छात्रों पर अभूतपूर्व हमला बोलते हुए कहा कि परिसर में 'राष्ट्र विरोधी ताकतों' का समर्थन करने वाले लोगों का 'सख्त इलाज' किये जाने की जरूरत है।

अधिकारी पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय और कॉलेज (प्रशासन एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का बचाव कर रहे थे, जिसे राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया और सदस्यों ने 171 - 15 मतों से इसे पारित कर दिया।

यह विधेयक सरकार को राज्य सरकार के कुल आठ विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का तबादला करने का अधिकार देता है जिसके तहत एक राज्य विश्वविद्यालय से दूसरे राज्य विश्वविद्यालय में तबादला किया जा सकेगा। अधिकारी ने सरकारी सेवा की शर्तों और प्रस्तावित तबादला व्यवस्था से नाखुश लोगों पर तीखा तंज कसते हुए उनसे नौकरी छोड़ने को कहा।

उन्होंने कहा, जिन लोगों को सरकारी नौकरियों की इन शर्तों से काफी परेशानी है, वे नौकरी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। कंधे पर झोला लटकाइए, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन जाइए और गणशक्ति (माकपा का मुखपत्र) बेचिए। कभी-कभार हाथ में टिन का डिब्बा लेकर न्यू मार्केट इलाके में घूमते हुए चंदा भी इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, जो लोग नियुक्ति देते हैं, उन्हें नियुक्ति की शर्तें तय करने का अधिकार भी होता है। नियुक्त किए गए लोगों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तबादले के प्रावधान के पीछे के तर्क के बारे में अधिकारी ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों को नए या कमजोर विश्वविद्यालयों में तैनात किया जा सकता है, ताकि इन संस्थानों को मजबूत किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल ऐसी तबादला नीति लागू करने वाला पहला राज्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही ऐसा प्रावधान मौजूद है। किशनजी और फलस्तीन से जुड़े नारों तथा लिखावट का विशेष रूप से जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा, यादवपुर में कला संकाय की दीवारों पर 'किशनजी, लाल सलाम' जैसे नारे लिखे दिखाई देते हैं। उस व्यक्ति ने 1,000 से अधिक निर्दोष लोगों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की हत्या की थी। 'फ्री फलस्तीन' भी लिखा जा रहा है। हम प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम, मातंगिनी हाजरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर ऐसी चीजों को होने की अनुमति नहीं देंगे। अधिकारी ने कहा कि यादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) को केंद्र और राज्य सरकार से 1,300 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा, लेकिन अगर वहां 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' का नारा लिखा जाएगा तो 'हम उनके टुकड़े-टुकड़े कर देंगे'। पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय एवं कॉलेज (प्रशासन और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को राज्य मंत्रिमंडल ने आठ सितंबर को मंजूरी दी थी।

अधिकारियों ने बताया कि इसमें 2017 के मौजूदा कानून की धारा 14ए में एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव था, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में तबादला किया जा सके।

अधिकारियों ने कहा कि इस प्रावधान के तहत कुलाधिपति को राज्य सरकार से परामर्श के बाद एक विश्वविद्यालय के कर्मचारी को दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा, जब ऐसा कदम प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक माना जाए।

सार समाचार

फर्रुखाबाद-फिरोजाबाद में संरक्षित होगी नीब करोरी बाबा की विरासत

फर्रुखाबाद,एजेंसी। उत्तर प्रदेश में संत नीब करोरी बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों को विकसित कर उनकी आध्यात्मिक विरासत को देश-दुनिया के श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की दिशा में पर्यटन विभाग ने पहल शुरू की है। फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद में पर्यटन सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचे के विकास पर करीब 12.93 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़कर 'नीब करोरी बाबा सर्किट' विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए 'बाबा नीब करोरी' के पांच विशेष टूर पैकेज भी शुरू किए हैं।

मराठवाड़ा में कुनबी प्रमाण पत्र शिविर शुरू करेगी सरकार

पुणे,एजेंसी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के अनिश्चितकालीन आंदोलन के 13वें दिन प्रवेश करने के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी आठ जिलों में पात्र आवेदकों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का फैसला किया है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि प्रशासन बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए पूरी तरह तत्पर है।

बावनकुले ने संवाददाताओं से कहा कि कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने का यह कदम आंदोलन की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया और ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर लागू की जा रही एक नीतिगत व्यवस्था है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के लगभग 58 लाख पुराने रिकॉर्ड और आंदोलन के दौरान सामने आई 49,000 नयी प्रविष्टियों के गहन सत्यापन किया जाएगा।

जोखिमपूर्ण भवनों की जांच में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही: मुख्यमंत्री साय

रायपुर, एजेंसी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जिलों में हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर, स्कूल और बड़े शैक्षणिक भवनों का तत्काल निरीक्षण एवं सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि जोखिमपूर्ण भवनों की जांच और सुरक्षा मानकों के पालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। साय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि विद्यार्थियों और नागरिकों की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रशासन को किसी दुर्घटना का इंतजार करने के बजाय संभावित खतरों की पहले पहचान कर समय रहते प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने स्कूलों, पुस्तकालयों, छात्रावासों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थित पुराने और जर्जर भवनों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन भवनों से जनहानि की आशंका है, उनकी पहचान कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिलों में इस अभियान की नियमित निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों और विद्यार्थियों से जुड़े संस्थानों में सुरक्षा मानकों के पालन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलों में शिकायत या दुर्घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय सतत निरीक्षण और समय रहते सुधार की व्यवस्था विकसित की जाए। साय ने बैठक में अवैध एवं मिलावटी शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन के खिलाफ भी प्रदेशव्यापी सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को संयुक्त टीमें बनाकर संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी और वैधानिक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने दूसरे राज्यों से अवैध शराब की आवक रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने तथा पुलिस और आबकारी विभाग के बीच सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशों पर तत्काल अमल शुरू करने और की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव रजत बंसल और संयुक्त सचिव प्रभात मलिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुझे भाजपा से निकलवाने की साजिश रची जा रही: कौशल किशोर

लखनऊ, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे मोहनलाल गंज संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सरकार में बैठे लोग उन्हें पार्टी से निकलवाने की साजिश रच रहे हैं और ऐसी परिस्थितियां बनायी जा रही हैं कि वह ख़ुद पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो जायें।

ऐसे लोग आने वाले चुनाव में पार्टी का भारी नुकसान करेंगे, जिसका ख़ामियाज़ा पूरी सबको भुगतना पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यूनीवार्ता से बातचीत में कहा कि पार्टी और सरकार के भीतर कुछ लोग हैं, जिनको उनका कद और उनकी लोकप्रियता रास नहीं आ रही है। इसलिए वे लोग उनके ख़िलाफ़ लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि वह छोड़कर चले जायें।

किशोर से यह पूछे जाने पर कि आप पार्टी से इतने नाराज़ क्यों हैं, उन्होंने कहा,हमने पार्टी को अपना बहुमूल्य समय और योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़े थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत से भाजपा को खड़ा किया है। इसी का नतीजा था कि हमने अपनी संसदीय सीट की सभी विधानसभा सीटें जीताकर पार्टी के खाते में डालने का काम किया था।

किशोर से यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें पार्टी के भीतर ही अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने कहा, बिल्कुल मेरी उपेक्षा की जा रही है। सही बात कहने की सजा दी जा रही है। पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता। कोई कार्यक्रम करता हूं, तो पार्टी के नेताओं को आने से रोक दिया जाता है। ऐसे में अपने आत्मसम्मान की बची खुची लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने अपनी मंशा से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अभी मुझे इंतजार करने के लिए बोला गया है। आगे जैसी परिस्थितियां बनेंगी, वैसा कदम उठाएंगे।

दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज से पूर्व भाजपा सांसद कौशल किशोर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नयी चर्चा छेड़ दी थी।

कांग्रेस नेता सत्ता में बिताए दिन भूल गए जनता नहीं: सैनी

चंडीगढ़, एजेंसी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रहा है। लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत में सैनी ने कांग्रेस नेताओं के काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचने पर कहा कि कांग्रेस नेता भले ही अपने शासनकाल की कमियां भूल गए हों, लेकिन जनता उन्हें नहीं भूली है। कांग्रेस शासन के दौरान बुजुर्गों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगती थीं और युवाओं को रोजगार के लिए परेशान होना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें घोषणाओं पर निर्भर रही हैं, जबकि भाजपा सरकार का ध्यान योजनाओं को जमीन पर लागू करने और लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने पर है। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है। फिलहाल एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं इसके दायरे में हैं। 17 सितंबर से इसका दायरा बढ़ाकर 18 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को शामिल करने के लिए पंजीकरण शुरू होगा।

सैनी ने कहा कि हरियाणा युवाओं को खेल और शिक्षा से जोड़कर नशे से दूर रखने के लिए काम कर रहा है। जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष विकास कार्यों को लेकर राजनीति कर रहा है। जहां सरकार विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी कर रही है, वहां विपक्षी नेता जाकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शासन और सार्वजनिक सेवाओं को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया गया है।

सागर शराबकांड के तीन आरोपितों के पांच मकानों पर चला बुलडोजर

सागर, एजेंसी।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में प्रशासन ने गुरुवार को आरोपितों की संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बंडा के वार्ड नंबर 11 और 12 में तीन आरोपितों से जुड़े पांच मकानों के कथित अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाया। कार्रवाई के दौरान तीन जेसीबी मशीनें और भारी पुलिस बल तैनात रहा।

प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई मुख्य आरोपी बताए जा रहे चंद्रभान सिंह राजपूत उर्फ चंदू, आशीष साहू और मनीष लोधी से जुड़े निर्माणों पर की गई। कुल पांच मकानों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीम सबसे पहले चंद्रभान सिंह राजपूत के मकान पर पहुंची। इसके बाद आशीष साहू और मनीष लोधी से जुड़े मकानों पर भी कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड और जांच के आधार पर चिह्नित किए गए कथित अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आशीष साहू के एक मकान को पूरी तरह गिरा दिया गया है। मनीष लोधी से जुड़े तीन मकानों में भी कथित अवैध हिस्से हटाए गए।

जनता ने भाजपा को नकारा: जूली

अलवर,एजेंसी। राजस्थान में नगर निगम चुनाव के मतदान के बाद अब बोर्ड गठन को लेकर सियासी दावों का दौर तेज हो गया है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली ने दावा करते हुए कहा है कि अलवर नगर निगम में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नकार दिया है और कांग्रेस को शहर की जनता का स्पष्ट समर्थन मिला है। जूली ने कहा कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट हैं और चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी आश्वस्त है। उन्होंने दावा किया कि जनता का रुझान और पार्टी के सर्वेक्षण कांग्रेस के पक्ष में हैं।

उनके मुताबिक अलवर में कांग्रेस बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति में है। जूली ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में भाजपा सरकार और नगर निगम ने अलवर शहर के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया।

रौन में कल लगेगा मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का पांचवां शिविर

अमरकांत सिंह चौहान

भिण्ड, साहस समाचार। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत भिण्ड जिले का पांचवां जनविश्वास शिविर शुक्रवार, 11 सितंबर को रौन तहसील स्थित शासकीय वेयरहाउस में आयोजित होगा। शिविर में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा तथा नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी।

शिविर में खाद्यान्न पर्ची, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, फार्मर आईडी, समग्र आईडी, आधार कार्ड निर्माण एवं अद्यतन तथा संबल पंजीयन जैसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। राजस्व, कृषक कल्याण, उद्योग, पशुपालन, उद्यानिकी, श्रम, ऊर्जा, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। नागरिक इन स्टॉलों पर लंबित शिकायतों के निराकरण के साथ नई समस्याओं और योजनाओं से संबंधित आवेदन भी दे सकेंगे। जनसुनवाई के दौरान जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष समस्याएं सीधे रखने की सुविधा होगी।

शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। यहां मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, दंत एवं नेत्र रोगों के अलावा ब्लड प्रेशर और मधुमेह की जांच, चिकित्सकीय परामर्श तथा आवश्यक दवाओं का वितरण किया जाएगा। पैथोलॉजी और एक्स-रे जांच की सुविधा भी रहेगी। इसके अलावा आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई हैं।

शिविर की तैयारियों के लिए क्षेत्र को आठ सेक्टरों में बांटकर क्लस्टर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायतों का पूर्व भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

पिछले तीस वर्षों से बिहार के जल हितों की अनदेखी हो रही है: संजय झा

पटना,एजेंसी। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने गुरुवार को कहा है कि पिछले 30 वर्षों से बिहार के जल हितों की अनदेखी हो रही है और अब राज्य के साथ और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जदयू नेता ने कहा कि फरक्का जल संधि के कारण बिहार को एक ओर पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर गंगा में गाद की समस्या बढ़ने से राज्य में बाढ़ की समस्या भी गंभीर हुई है।

झा ने आज जदयू प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि फरक्का जल संधि से संबंधित 'नीतीश संवाद' कार्यक्रम गंगा बेसिन से जुड़े राज्य के 12 जिलों में बिहार के जल हितों के प्रति जनजागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रथम चरण में चार जिलों में कार्यक्रम के दौरान जिस तरह लोगों की भागीदारी हुई।

सड़क हादसे में मां-बेटे समेत दो की मौत, दो गंभीर

शशिकांत गोयल

भिण्ड, साहस समाचार। लहार थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे लहार-सिकरी मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में मां-बेटे समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसा हीरापुरा गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत के बाद हुआ।

जानकारी के अनुसार लालपुरा निवासी 20 वर्षीय दिग्विजय पुत्र रामनरेश विश्वकर्मा अपनी मां गुड्डी देवी के साथ मोटरसाइकिल से लहार की ओर जा रहा था। इसी दौरान हीरापुरा गांव के पास सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि दिग्विजय को सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसकी मां गुड्डी देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी भी जान नहीं बच सकी। एक ही हादसे में मां-बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। दूसरी मोटरसाइकिल पर भगवान सिंह कारीगर पुत्र चिंतई जाटव, निवासी वार्ड नंबर 14 लहार और अमन सिंह राजावत सवार बताए गए हैं। दोनों भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तत्काल लहार के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। भगवान सिंह की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि अमन सिंह का उपचार जारी है।

हादसे के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक दूसरी मोटरसाइकिल पर लोहे का गेट रखा हुआ था। इसी दौरान दोनों मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने टक्कर हुई। हालांकि बाइक पर रखे सामान की वजह से दुर्घटना किस तरह हुई और हादसे का वास्तविक कारण क्या रहा, यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। हादसे के बाद कुछ लोगों द्वारा घायलों के नशे में होने की बात भी कही गई, लेकिन फिलहाल पुलिस अथवा किसी अधिकृत अधिकारी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में नशे को दुर्घटना का कारण मानना अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस की जांच और आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हादसे की सूचना मिलते ही लहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की तथा दोनों क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को अपने कब्जे में लेकर हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

100 करोड़ की सीवरेज परियोजना में बदलाव की तैयारी

बैतूल,एजेंसी। मध्यप्रदेश के बैतूल शहर में करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट परियोजना को लेकर असमंजस की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान होने वाली खुदाई और नागरिकों को संभावित परेशानी को देखते हुए इसके मौजूदा स्वरूप में बदलाव की तैयारी की जा रही है। नगर पालिका अधिकारियों ने परियोजना से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों से जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है। प्रस्तावित परियोजना के तहत शहर में सीवरेज नेटवर्क बिछाने के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाना है। जानकारी के अनुसार परियोजना नगर पालिका की ओर से अलग से मांग किए जाने के बजाय शासन स्तर से स्वीकृत कर आगे बढ़ाई गई है। नगर पालिका ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने के साथ निविदाएं भी आमंत्रित की हैं।

मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ के बलराम कृषि महोत्सव को किया वर्चुअली संबोधित

किसानों की खुशहाली से बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल, एजेंसी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि होती है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनकी समृद्धि बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को टीकमगढ़ में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुंदेलखंड अंचल की समृद्धि के लिए केन-बेतवा अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है। उनका संकल्प है कि पर्याप्त सिंचाई से उत्पादन में वृद्धि हो और किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किए जाएं। आने वाले समय में बुंदेलखंड अंचल की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ में पीतल की मूर्तियां बनाने वाले शिल्पी इस क्षेत्र की पहचान है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में टीकमगढ़ जिले में हो रहा कार्य अन्य जिलों के लिए उदाहरण बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बलराम कृषि महोत्सव में पधारे जनप्रतिनिधियों, किसानों और बहनों को श्रेष्ठ आयोजन के लिए तथा आने वाले पर्व-त्यौहारों की बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने बलराम कृषि महोत्सव में आये किसानों से चर्चा की, जो उन्नत कृषि के कार्य में संलग्न है। उन्होंने किसानों द्वारा किए जा रहे परिश्रम और नवाचारों की प्रशंसा की। उन्होंने विष्णु शर्मा अनंतपुरा को सब्जी उत्पादन और पॉली हाऊस निर्माण के साथ ही गौशाला के संचालन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री को बालचंद अहिरवार ने बताया कि वे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिससे लगभग 250 किसान बंधु जुड़े हैं। मनोहर लोधी और शशि लोधी ने प्राकृतिक खेती के अनुभव सुनाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जगदीश अहिरवार ने लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में की जा रही फूलों की खेती विशेष रूप से स्ट्रोबेरी, तरबूज, नीबू, अमरूद आदि के उत्पादन की जानकारी दी। अहिरवार ने बताया कि वे उद्यानिकी विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर यह कार्य कर रहे हैं और दो दर्जन व्यक्तियों को रोजगार भी दे रहे हैं। इसके साथ ही 15 गायों को पालते हुए दुग्ध उत्पादन से भी लाभ कमा रहे हैं। रमेश यादव ने बताया कि वे वर्ष 2005 से बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। लगभग 3 लाख क्विंटल बीज उत्पादन में सक्षम बने हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सुनीता बुंदेला ने मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में 5 केंद्र कार्य कर रहे हैं। यह कार्य परिश्रम आधारित है जिसके आर्थिक लाभ काफी हैं। मधुमक्खी पालन कार्य की विस्तृत जानकारी भी सुनीता बुंदेला द्वारा दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मधुमक्खी पालन कार्य में रानी मक्खी की भूमिका का उल्लेख आने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने तो रानी मक्खी नहीं देखी, लेकिन अपनी बहन सुनीता को मधुमक्खी पालन के कार्य से आर्थिक रूप से सक्षम होने और महारानी बनते हुए देखने का अवसर जरूर प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक, अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र यादव, कप्तान सिंह से भी चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में बलराम कृषि महोत्सव प्रारंभ किए गए हैं, जिनकी किसान कल्याण की दृष्टि से बहुत उपयोगिता है।

काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर बड़ी कार्रवाई, 6 ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड

रायपुर, एजेंसी।

छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में अत्यंत धीमी प्रगति और कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं लेने वाले 6 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की है। विभाग द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं होने पर बार-बार नोटिस जारी करने, अनुबंध अवधि बढ़ाने, ठेकेदारों द्वारा स्वयं शपथ पत्र देने के बावजूद काम नहीं करने तथा कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं लेने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर उनके पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। दो ठेकेदारों के पंजीयन भी निरस्त किए गए हैं।

राज्य शासन ने बस्तर की महत्वाकांक्षी सड़कों के निर्माण की धीमी गति और विलंब को देखते हुए व्यापक समीक्षा के बाद वहां निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने में रूचि नहीं दिखाने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की है।

ये ठेकेदार बार-बार नोटिस जारी करने तथा स्वयं शपथ पत्र देने के बावजूद काम नहीं कर रहे थे। इनके द्वारा निर्माणाधीन सड़कों और पुलों को पूर्ण करने में रूचि नहीं ली जा रही थे। राज्य शासन ने इन कार्रवाईयों को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण में कोताही, लापरवाही और अनुबंधों के उल्लंघन पर ठेकेदार श्री के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन अ-नवीनीकरण के आदेश जारी किए गए हैं।

विभाग ने सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा के कार्यों में हीला-हवाला को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार श्री के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन को भी निरस्त कर दिया है।

ईस्ट जोन के लिए खत्म हुआ 13 साल का सूखा, जीता दलीप ट्रॉफी का खिताब

दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ ड्रॉ हुए मुकाबले में पहली पारी की बढ़त के आधार पर 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी अपने नाम की।

चेन्नई,एजेंसी। पूर्व क्षेत्र ने फाइनल में पूरी तरह से बनाए दबदबे को खिताबी जीत में तब्दील करते हुए बृहस्पतिवार को यहां दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ ड्रॉ हुए मुकाबले में पहली पारी की बढ़त के आधार पर 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी अपने नाम की। पूर्व क्षेत्र ने अपनी दूसरी पारी में सात विकेट पर 388 रन बनाए जिससे उसकी कुल बढ़त 760 रन तक पहुंच गई। इसके बाद मुकाबला ड्रॉ घोषित कर दिया गया।

मोहम्मद कोनेन कुरैशी ने इस मुकाबले में शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने नाबाद 116 रन बनाए जो उनके केवल दो मैच पुराने प्रथम श्रेणी करियर का पहला शतक है। कुरैशी ने अनुकूल रॉय (64) के साथ सातवें विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की। उन्होंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सीवी मिलिंद की गेंद पर दो रन लेकर 179 गेंद में अपना शतक पूरा किया। हालांकि दोनों टीम के खिलाड़ियों के दोपहर दो बजकर 10 मिनट पर हाथ मिलाने और मैच ड्रॉ घोषित होने से काफी पहले ही पूर्व क्षेत्र ने पहली पारी में 708 रन बनाकर खिताब लगभग तय कर लिया था।

इस विशाल स्कोर की बदौलत टीम ने पहली पारी में 372 रन की बढ़त हासिल की थी। पूर्व क्षेत्र ने दूसरी पारी में भी दक्षिण क्षेत्र के गेंदबाजों को बेअसर साबित किया। पांच विकेट पर 212 रन से दिन की शुरुआत करने वाली इशान किशन की अगुआई वाली टीम को पहली पारी की तरह ही दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे दक्षिण क्षेत्र के गेंदबाज अधिक परेशान नहीं कर पाए। अनुभवी मोहम्मद सिराज कुछ समय के लिए पूरे जोश, तेजी और आक्रामकता के साथ गेंदबाजी करने आए। व्यक्तिगत रूप से उनका प्रयास संतोषजनक रहा लेकिन टीम के लिहाज से वह बेअसर साबित हुए। सिराज को दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला और दक्षिण क्षेत्र का कमजोर बल्लेबाजी प्रदर्शन भी उसके टीम चयन की खामियों को उजागर करता है।

दक्षिण क्षेत्र प्रबंधन ने करुण नायर, मयंक अग्रवाल और साई किशोर जैसे फॉर्म में चल रहे तथा अनुभवी खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया और उनकी जगह शामिल किए गए खिलाड़ी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। इसके विपरीत पूर्व क्षेत्र के कई खिलाड़ियों ने अवसर का पूरा फायदा उठाया। कप्तान किशन ने पहली पारी में शानदार 270 रन बनाकर लाल गेंद के क्रिकेट में अपनी तैयारी का मजबूत संकेत दिया। वहीं अपने 100वें प्रथम श्रेणी मैच में खेल रहे अनुभवी मोहम्मद शमी ने भी जुझारू प्रदर्शन करते हुए कुछ युवा खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। कुमार कुशाग्र ने छठा प्रथम श्रेणी शतक लगाया जबकि झारखंड के उनके साथी शिखर मोहन ने तकनीक और संयम से भरी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।

किशन की कप्तानी भी शानदार रही। टीम के विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद टीम का प्राथमिक लक्ष्य स्पष्ट था, दक्षिण क्षेत्र के सभी 10 विकेट हासिल करना और पहली पारी की बढ़त सुनिश्चित करना। किशन ने अपनी रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब आप टीम के कप्तान होते हैं तो सबसे पहली चीज परिस्थितियों को समझना होती है। हमने लगभग दो दिन बल्लेबाजी की। अब एक इकाई के तौर पर हम जानते थे कि यह मूल रूप से पहली पारी का मुकाबला है।

बुमराह फ़िट, हर्षित की जगह यश ठाकुर टीम में शामिल

मुम्बई,एजेंसी। भारतीय चयन समिति ने अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ तीन मैचों की टी20 सीरीज़ और 2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम में हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर को शामिल किया है। वहीं सीनियर तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फ़िट होकर मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उनका चयन उनकी फ़िटनेस अपडेट पर आधारित था। तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (सीओई) में रिहैब के दौरान अच्छी तरह ठीक हो रहे थे।

लेकिन 7 सितंबर को मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाज़ी करते हुए उनकी मांसपेशी में खिंचाव आ गया। जिसके बाद उन्हें दोनों प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया गया है। विदर्भ के 27 साल के तेज़ गेंदबाज़ यश ठाकुर ने हाल ही में जुलाई में ज़िम्बाब्वे दौरे पर भारत के लिए टी 20 डेब्यू किया था। उन्होंने दो मैच खेले थे जिसमें चार विकेट लिए थे। वह 50 सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 7.04 की शानदार इकॉनमी रेट से 81 विकेट लिए हैं। क्रिकइंफो को मिली जानकारी के मुताबिक़ बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी कल यानी शुक्रवार को दल के साथ दिल्ली में जुड़ रहे हैं।

उनके अलावा दलीप ट्रॉफ़ी फ़ाइनल खेल रहे तीन और खिलाड़ी भी दल के साथ जुड़ जाएंगे। अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ टी20 के लिए भारत की अपडेटेड टीम श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर

2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल। श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर।

फीफा आसियान कप 24 सितंबर से, हिस्सा लेंगे 14 देश

नई दिल्ली,एजेंसी। पहला फीफा आसियान कप सितंबर-अक्टूबर के मौजूदा पुरुषों के इंटरनेशनल मैच कैलेंडर के दौरान आयोजित किया जाएगा। 14 राष्ट्रीय टीमें - जिनमें सभी 11 आसियान सदस्य और तीन मेहमान टीमें शामिल हैं - दो डिवीज़न में मुकाबला करेंगी। इंडोनेशिया और हांगकांग को टूर्नामेंट के पहले संस्करण के लिए मेज़बान देश के तौर पर कन्फर्म किया गया है। फीफा को पहले फीफा आसियान कप की अहम जानकारी देते हुए खुशी हो रही है, जो 24 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया और बड़े क्षेत्र के मेहमान देशों की राष्ट्रीय टीमों को एक साथ लाएगा। इस साल का मुकाबला इंडोनेशिया के बांडुंग और जकार्ता और हांगकांग में आयोजित किया जाएगा।

टूर्नामेंट में 14 टीमें शामिल होंगी - एसोसिएशन ऑफ़ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के सभी 11 सदस्य और तीन मेहमान टीमें - जो एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड फ़ॉर्मेट में मुकाबला करेंगी जिसे हाई-क्वालिटी इंटरनेशनल फ़ुटबॉल देने, क्षेत्रीय संबंधों को मज़बूत करने और फ़ैन्स के लिए खेल से जुड़ने के नए मौके बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फीफा आसियान कप में दो डिवीज़न होंगे। डिवीज़न 1, जिसकी मेज़बानी इंडोनेशिया करेगा, में मलेशिया, फ़िलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और दो मेहमान देश बंगलादेश और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। डिवीज़न 2 में, मेज़बान हांगकांग (जो एक मेहमान प्रतिभागी भी है) के अलावा, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और तिमोर-लेस्ते दूसरे टियर में शामिल होंगे।

पाकिस्तान को 19-0 से रौंदकर महिला टीम सेमीफाइनल में

मोकी,एजेंसी। भारत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बृहस्पतिवार को यहां पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत ने शुरू से लेकर आखिर तक दबदबा बनाए रखा और आक्रामक खेल का नजारा पेश करते हुए टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की। भारत ने जहां 19 गोल किए, 18 पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक हासिल किया, वहीं पाकिस्तान एक भी गोल, पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी स्ट्रोक हासिल नहीं कर पाया।

भारत शनिवार को सेमीफाइनल में कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगा। भारत ने पहले क्वार्टर में पांच, दूसरे क्वार्टर में भी पांच, तीसरे क्वार्टर में तीन और अंतिम क्वार्टर में छह गोल करके बड़ी जीत दर्ज करके शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत को शुरुआती पांच मिनट के भीतर दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, हालांकि वह इनका फायदा नहीं उठा पाया। भारत ने छठे मिनट में गोल दाग दिया था, लेकिन रेफरल के बाद गोल को अमान्य घोषित कर दिया गया।

भारत ने अपना दबाव बनाए रखा और एक मिनट बाद ही उसे एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार पूजा साहू ने कोई गलती नहीं की और भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। भारत ने नौवें मिनट में रोशनी ऐंद के मैदानी गोल से अपनी बढ़त को तुरंत दोगुना कर दिया। इस क्वार्टर में भारत को मिले चौथे पेनल्टी कॉर्नर पर तनुश्री काडू ने 11वें मिनट में डिफ्लेक्शन के जरिए गोल करके स्कोर 3-0 कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने सर्कल के अंदर फाउल किया, जिससे भारत को 13वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिसे सुखवीर कौर ने गोल में बदला। सानिका माने ने इसके तुरंत बाद मैदानी गोल दागकर पहले क्वार्टर के बाद स्कोर 5-0 कर दिया।

मधु सिदार ने 16वें मिनट में मैदानी गोल किया, जिसके दो मिनट बाद गीता यादव ने एक और गोल करके भारत की बढ़त को 7-0 तक पहुंचा दिया। सानिका ने 23वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। इसके बाद तनुजा टोप्पो ने 25वें मिनट में मैच का अपना पहला गोल दागा। भारत ने लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। पूजा मलिक ने 27वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलकर हाफ टाइम से पहले स्कोर 10-0 कर दिया।

तीसरे क्वार्टर के शुरू में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर पूर्णिमा यादव ने डिफ्लेक्शन से गोल करके स्कोर 11-0 कर दिया। मधु ने 39वें मिनट में और सुप्रिया ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। कृष्णा शर्मा ने 48वें मिनट में मैदानी गोल किया।

विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीजः भारत ने चार स्वर्ण सहित 15 पदक जीते

अहमदाबाद,एजेंसी। मेजबान भारत ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे चरण में चार स्वर्ण, तीन रजत और आठ कांस्य सहित कुल 15 पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। पदक तालिका में हालांकि भारत पांच स्वर्ण पदक जीतने वाले चेक गणराज्य से पीछे दूसरे स्थान पर रहा। चीन ने दो स्वर्ण, छह रजत और पांच कांस्य पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता ने भारत के पैरा तीरंदाजों को 18 से 24 अक्टूबर तक आइची-नागोया में होने वाले एशियाई पैरा खेलों के लिए तैयारी का अच्छा मौका मिला।

भारत की स्वर्ण पदक जीतने की मुहिम का नेतृत्व पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ने किया। उन्होंने विजय सुंडी के साथ मिलकर पैरा रिकर्व पुरुष युगल का खिताब जीता। हरविंदर ने प्रतियोगिता अंतिम दिन भावना के साथ जोड़ी बनाकर पैरा रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार ने पैरा कंपाउंड पुरुष युगल में भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया, जिसके बाद विश्व चैंपियन और पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता शीतल देवी ने पैरा कंपाउंड महिला वर्ग में व्यक्तिगत खिताब जीता। सरिता ने भी कांस्य पदक जीतकर शीतल देवी के साथ पोडियम पर अपनी जगह बनाई। भारत के तीन रजत पदक भावना और पूजा ने पैरा रिकर्व महिला युगल में, तन्वी इंगले ने दृष्टिबाधित वर्ग में और स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने महिला प्रथम श्रेणी की मिश्रित टीम स्पर्धा में जीते।

बिजनेस

सोने और चांदी में मिलाजुला कारोबार

मुंबई,एजेंसी। सोने और चांदी में गुरुवार को मिलाजुला कारोबार हो रहा है, यह दिखाता है कि निवेशक दोनों कीमती धातुओं पर फैसला लेने से पहले अमेरिका के महंगाई के डेटा का इंतजार कर रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,53,763 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले मामूली कमजोरी के साथ 1,53,581 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।

नवी यूपीआई ने इंडसइंड बैंक के साथ किया करार

मुंबई,एजेंसी। नवी यूपीआई ने अपने यूपीआई ऑपरेशन से जुड़ी प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए गुरुवार को इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की। यहां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नवी लिमिटेड और इंडसइंड बैंक ने इस साझेदारी की घोषणा की।

बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों में लिवाली से प्रमुख सूचकांकों में तेजी

मुंबई,एजेंसी। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनियों में लिवाली से गुरुवार को घरेलू शेयर बाजारों में प्रमुख सूचकांकों में तेजी रही, हालांकि वृहत बाजार में बिकवाली का जोर देखा गया। बीएसई की 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज पूरे दिन सीमित दायरे में कभी लाल तो कभी हरे निशान में रहा। यह ऊपर 74,910 अंक और नीचे 74,599 अंक को छूने के बाद अंत में पिछले कारोबारी दिवस के मुकाबले 138.36 अंक (0.19 प्रतिशत) चढ़कर 74,902.59 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी-50 सूचकांक का ग्राफ भी लगभग सेंसेक्स जैसा ही रहा। यह अंत में 46.30 अंक यानी 0.20 प्रतिशत ऊपर 23,477.80 अंक पर रहा। इससे पहले लगातार तीन दिन गिरने के बाद प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए हैं।

वृहत बाजार में गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.36 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.07 प्रतिशत फिसल गया। सेक्टर आधारित सूचकांकों में निफ्टी बैंक 0.31 प्रतिशत और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.57 प्रतिशत मजबूत हुआ। ऑटो, धातु, फार्मा और स्वास्थ्य समूहों के सूचकांक गिर गए। एनएसई में जिन 3,666 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें से 2,077 के शेयर नीचे बंद हुए जबकि 1,466 कंपनियों के शेयरों में तेजी रही। अन्य 123 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित रहे।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 15 के शेयर लाल निशान में रहे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर 2.43 प्रतिशत के करीब टूट गया। टाटा स्टील में 1.38 प्रतिशत और ट्रेंट में 1.12 प्रतिशत की गिरावट रही। आईटीसी, अडानी पोर्ट्स, बीईएल, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनीलिवर और इंफोसिस के शेयर भी नीचे बंद हुए। पावरग्रिड में 2.27 फीसदी की तेजी देखी गई। एक्सिस बैंक का शेयर 1.65 प्रतिशत, अल्ट्राटेक सीमेंट का 1.44, एनटीपीसी का 1.13, टेक महिंद्रा का 1.09, भारती एयरटेल का 1.00 और एचडीएफसी बैंक का 0.98 प्रतिशत ऊपर रहा।

एलएंडटी, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, टाइटन और टीसीएस के शेयर भी बढ़त में रहे। वैश्विक स्तर पर हांगकांग का हैंग सेंग 1.27 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.43 प्रतिशत गिर गया। जापान के निक्केई में 0.20 प्रतिशत की तेजी रही।

हीरो मोटर्स शेयर बाजार में होगी सूचीबद्ध, 16 सितंबर को खुलेगा आईपीओ

नई दिल्ली,एजेंसी। वाहनों के लिए कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी हीरो मोटर्स लिमिटेड का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 16 सितंबर को खुलेगा और 18 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि 10 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर के लिए मूल्य का दायरा 79 रुपये से 84 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशक कम से कम 178 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और उसके बाद 178 इक्विटी शेयरों के गुणांक में बोली लगा सकते हैं।

आईपीओ के तहत 600 करोड़ रुपये तक के नये शेयर जारी किए जाएंगे। प्रवर्तक ओपी मुंजाल होल्डिंग्स और हीरो साइकिल्स लिमिटेड अपनी हिस्सेदारियों में से 400 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) के तहत बेचेंगे। इस प्रकार आईपीओ से कंपनी को 1,000 करोड़ रुपये तक की आमदनी की उम्मीद है। हीरो मोटर्स की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि फ्रेश इश्यू से मिलने वाली 190 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया ऋण के पूरे या आंशिक भुगतान/अग्रिम भुगतान के लिए किया जाएगा।

अन्य 200 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी के पूंजीगत खर्च के लिए किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी मशीनरी की खरीद, अब तक अघोषित अधिग्रहणों तथा अन्य रणनीतिक पहलों के जरिये विस्तार, और सामान्य कामकाज शामिल हैं। कंपनी देश की प्रमुख वाहन प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। वह अमेरिका, यूरोप, भारत और आसियान देशों में वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी वाले पावरट्रेन समाधान बनाती है। वह पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी पावरट्रेन बनाती है।

एसोचैम ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक दशक के काम को सराहा

नई दिल्ली,एजेंसी। उद्योग संगठन एसोचैम ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के एक दशक के काम की तारीफ करते हुए गुरुवार को कहा कि उसने सकल ऋण मंजूरी में लक्ष्य से 43 प्रतिशत अधिक हासिल कर अपनी दक्षता का प्रमाण दिया है। एसोचैम के ग्लोबल रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी सेंटर की रिपोर्ट 'ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंकः कैटलाइज़िंग द न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर' के अनुसार, 2022-2026 की अवधि के लिए 30 अरब डॉलर के लक्ष्य के मुकाबले एनडीबी ने 42.9 अरब डॉलर की सकल ऋण मंजूरी हासिल की है।

यह लक्ष्य से 12.9 अरब डॉलर (43 प्रतिशत) अधिक है। वहीं, शुद्ध ऋण मंजूरी 35.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो लक्ष्य से 5.6 अरब डॉलर अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्त पोषण से हरित ऊर्जा, परिवहन, पानी और साफ-सफाई, सामाजिक अवसंरचना और अन्य हरित विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी लगभग 140 परियोजनाओं को मदद मिली है। अलग-अलग उधार लेने वालों की क्रेडिट प्रोफाइल पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय एनडीबी खुद की निवेश ग्रेड रेटिंग का इस्तेमाल कर विकासशील सदस्य देशों को अधिक लाभकारी वित्तीय लागत पर और लंबी अवधि के लिए ऋण दे पाता है।

एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा ने एनडीबी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बहुत ही प्रतिस्पर्धी दरों पर बुनियादी ढांचों के विकास के लिए ऋण दे सकता है। उसे एसएंडपी से एए प्लस, फिच से एए और जेसीआरए/सीसीएक्सआई से एएए जैसी मजबूत अंतरराष्ट्रीय साख रेटिंग का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि यह उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा फायदा है जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और हरित विकास में निवेश कर रही हैं।

एनडीबी की तारीफ करते हुए एसोचैम ने कहा है कि वह एक मजबूत आधार के साथ अपने दूसरे दशक में कदम रख रहा है। उसके पास वित्त पोषण का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, मजबूत साख रेटिंग, सदस्यों का बढ़ता दायरा और हरित ऊर्जा, परिवहन, पेयजल, सामाजिक बुनियादी ढांचा और डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना जैसे उभरते क्षेत्रों में विस्तृत पोर्टफोलियो है।

ग्रामीण ऋण व्यवस्था में एआई का इस्तेमाल बढ़ाएगा नाबार्ड

मुंबई,एजेंसी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण वित्तीय सेवाओं को अधिक तेज, सुलभ और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। नाबार्ड के चेयरमैन शाजी कृष्णन वी ने गुरुवार को कहा कि संस्था ऑन-डिमांड किसान क्रेडिट लोन उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मॉडल विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों और ग्रामीण परिवारों तक समय पर ऋण पहुंचाना तथा ग्रामीण वित्तीय प्रणाली को अधिक डिजिटल और प्रभावी बनाना है। मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' के दूसरे दिन अपने संबोधन में कृष्णन ने कहा कि कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण वित्तीय संस्थान अब डिजिटल ऋण प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, ताकि किसानों को जरूरत के समय आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की दूरी कम करने की मजबूत नींव तैयार की है। कृष्णन के अनुसार, भारत की लगभग 45 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए देश की तेज आर्थिक वृद्धि के लिए समावेशी विकास बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा, यदि भारत को तेजी से आगे बढ़ना है तो समाज के हर वर्ग का विकास जरूरी है।

नाबार्ड के चेयरमैन ने आगे कहा कि अब अगला कदम आधार जैसी पहचान प्रणालियों को आर्थिक गतिविधियों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना है, ताकि किसानों और ग्रामीण नागरिकों को अधिक आसानी से वित्तीय सेवाएं मिल सकें।

उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए विकसित किए जा रहे एग्री स्टैक की भी चर्चा की। एग्री स्टैक में पहचान संबंधी जानकारी, भूमि रिकॉर्ड और फसल संबंधी डेटा जैसे विभिन्न स्तर शामिल हैं, जो कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत डिजिटल आधार तैयार कर रहे हैं।

कृष्णन ने कहा कि एग्री स्टैक के साथ एक सशक्त वित्तीय ढांचे की भी आवश्यकता है, ताकि सही समय और सही स्थान पर किसानों को उपयुक्त वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि बागवानी, मत्स्य पालन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में भी डिजिटलीकरण की गति बढ़ रही है। बागवानी क्षेत्र में जलवायु अनुकूलता और उत्पादों की ट्रेसबिलिटी यानी स्रोत की पहचान महत्वपूर्ण होती जा रही है, जबकि मत्स्य क्षेत्र में भी ट्रेसबिलिटी अब एक प्रमुख आवश्यकता बनकर उभर रही है।

एक शादी में पहुंचीं और बदल गई किस्मत

यशराज की फिल्म से ट्यूलिप जोशी का बॉलीवुड डेब्यू

मुंबई। ट्यूलिप जोशी उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिनकी बॉलीवुड में एंट्री एक खास संयोग से हुई थी। 2002 में जब वह पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आईं तो उनके सामने यशराज फिल्म्स जैसा बड़ा बैनर था और फिल्म थी 'मेरे यार की शादी है'। नई एक्ट्रेस के लिए इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। फिल्म में उनके साथ उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और बिपाशा बसु जैसे कलाकार थे। ट्यूलिप की मासूमियत और सादगी भरे अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन इस डेब्यू के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि ट्यूलिप खुद फिल्म इंडस्ट्री में आने की योजना नहीं बना रही थीं। एक शादी में जाना उनके लिए ऐसा मोड़ लेकर आया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।

ट्यूलिप जोशी का जन्म 11 सितंबर 1979 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता गुजराती हिंदू थे, जबकि उनकी मां अर्मेनियाई-लेबनीज क्रिश्चियन थीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्यूलिप ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वह इस प्रतियोगिता की विजेता नहीं बनीं, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में उनके लिए रास्ते खुलने लगे। उस समय उनका सपना एक्ट्रेस बनना नहीं था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वह स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहती थीं।ट्यूलिप की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब वह एक शादी में शामिल होने गई थीं। यह शादी फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना की थी।

ट्यूलिप वहां लड़की वालों की तरफ से शामिल हुई थीं। शादी में उनकी पर्सनैलिटी पर आदित्य चोपड़ा की नजर पड़ी। इसके बाद उन्हें फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने का मौका मिला। ट्यूलिप ने भी बिना ज्यादा सोचे ऑडिशन दिया और उनका सेलेक्शन हो गया। इस तरह उन्हें सीधे यशराज फिल्म्स के बड़े बैनर के साथ काम करने का मौका मिला।

साल 2002 में 'मेरे यार की शादी है' रिलीज हुई। फिल्म में ट्यूलिप के साथ उदय चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। फिल्म ने उन्हें नई पहचान दी। बताया जाता है कि फिल्म में अपनी लाइन्स हिंदी में बोलने में उन्हें परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने हिंदी की ट्यूशन ली थी। पहली फिल्म की सफलता के बाद ट्यूलिप 'दिल मांगे मोर' में शाहिद कपूर और आयशा टाकिया के साथ नजर आईं। इसके बाद उन्होंने 'मातृभूमिः ए नेशन विदाउट वीमेन' जैसी गंभीर फिल्म की, जिसमें उन्होंने कल्कि का किरदार निभाया।

फिल्म में उनके काम को काफी सराहना मिली और अलग-अलग फिल्म फेस्टिवल में सम्मान भी मिला। ट्यूलिप ने बाद में खुद कहा था कि 'मातृभूमि' के बाद उन्होंने खुद में एक कलाकार के तौर पर बदलाव महसूस किया।

ट्यूलिप का सफर सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। वह 'मिशन 90 डेज', 'धोखा', 'सुपरस्टार', 'डैडी कूल', 'रनवे', 'बच्चन', 'जट्ट एयरवेज' और 'जय हो' जैसी फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने टीवी पर भी काम किया और 'एयरलाइंस' में पायलट का किरदार निभाया।

उनका आखिरी प्रमुख फिल्मी दौर 2010 के दशक में रहा और 'जय हो' में वह कैमियो में दिखाई दीं। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह बिजनेस वूमेन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तौर पर काम कर रही हैं।

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' का टीजर लॉन्च, हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का

मुंबई। अभिनेत्री यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' के मेकर्स ने गुरुवार को फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया। यह फिल्म डर के साथ-साथ कॉमेडी, फैंटेसी और पारिवारिक भावनाओं का एक अनोखा मिश्रण होगी।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, 'देवियों और सज्जनों, मोहिनी की तरफ से एक लिटिल रिक्वेस्ट। फिल्म 'नई नवेली' का टीजर रिलीज।'1 मिनट 31 सेकंड के टीजर में एक आम घरेलू माहौल के बीच अजीब और हास्यप्रद स्थितियां देखने को मिलती हैं। टीजर की शुरुआत एक सामान्य परिवार से होती है, जहां घर में आई नई नवेली दुल्हन (यामी गौतम) सबका दिल जीतती है तभी देवर को शक होता है और वह गंभीर आरोप लगाता है कि भाभी डायन है।

इसके बाद टीजर जैसे आगे बढ़ता है अभिनेत्री यामी गौतम की झलक देखने को मिलती है, जिसमें वे कहती हैं, 'दो डायन, तीन पिशाच और चार भूत को मैं सुबह नाश्ते में खा जाती हूं।'बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी फिल्म 'नई नवेली' को आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा (कलर येलो प्रोडक्शन और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज) मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की पटकथा हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार जी. वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है।

फिल्म की कहानी एक ऐसी दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देखने में बिल्कुल आदर्श लगती है। वह मेरठ के एक ऐसे परिवार में पहुंचती है, जहां पहले से ही काफी उथल-पुथल है। अपनी समझदारी और प्यार से वह इस बिखरे हुए परिवार को खुशहाल बनाने की कोशिश करती है। देखते ही देखते जिस घर में परेशानियां थीं, वहां खुशियां आने लगती हैं। इसी बीच उसके देवर को अपनी भाभी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि इतनी अच्छी और परफेक्ट भाभी के पीछे कोई राज जरूर है और कहीं वह वास्तव में डायन तो नहीं। यही शक फिल्म की कहानी को हास्य और रोमांच से जोड़ता है।

फिल्म में यामी गौतम धर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म इसी साल दशहरे के मौके पर 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बेटे आर्थर के 9वें जन्मदिन पर भावुक हुईं सेलिना जेटली, कहा- काश गले लगा पाती

मुंबई। अभिनेत्री सेलिना जेटली ने गुरुवार को बेटे आर्थर के जन्मदिन पर उसे विश किया। अभिनेत्री ने बेटे को याद करते हुए बताया कि वो आज के दिन बेटे आर्थर को याद तो कर रही हैं, लेकिन हर रोज वो अपने तीनों बच्चों से मिलने के लिए तरसती हैं।

सेलिना जेटली के तीन बेटे हैं, जिनके नाम विंस्टन, विराज और आर्थर हैं। विंस्टन हाग और विराज हाग जुड़वां बेटे हुए थे। वहीं, आर्थर हाग और शमशेर जुड़वा हुए थे, लेकिन जन्म के तुरंत बाद वर्ष 2017 में शमशेर का हृदय रोग के कारण निधन हो गया था। अभिनेत्री सेलिना जेटली ने इंस्टाग्राम पर अपने तीनों बच्चों के साथ तस्वीर पोस्ट कर लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, मेरे प्यारे आर्थर। मम्मी आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है। काश आज मैं तुम्हें गले लगा पाती, तुम्हारे पसंदीदा पानी पूरी बना पाती। मैं ये तस्वीरें

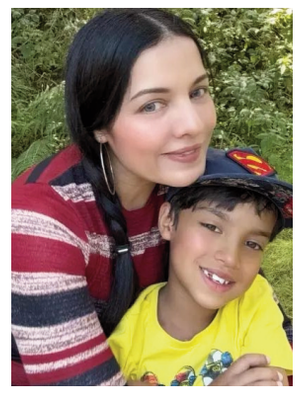

इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि उस प्यार को याद किया जाए जिसके साथ तुम इस दुनिया में आए थे।'

अभिनेत्री ने लिखा, 'जब से तुम और तुम्हारे भाई पैदा हुए हो, मेरी सबसे बड़ी खुशी दिन-रात तुम तीनों के लिए खुद को समर्पित करना रही है। आर्थु, जब तुम बिल्कुल छोटे थे तब तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं तुम्हारी नानी की देखभाल के लिए गई थी, जो कैंसर की आखिरी स्टेज में थीं। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मेरे बच्चे। मेरा प्यार हर पल तुम्हारे साथ था। मुझे याद है तुम्हारे नाना के अंतिम संस्कार में मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की थी, तब तुम और शमशेर मेरे पेट में थे। मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती थी। तुम्हारा मेरे बगल में आराम से सोना, मेरे बाल पकड़कर सोना, 11 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रिया छोड़ने तक की सारी यादें मेरे दिल में हैं।'

अभिनेत्री ने बताया कि बच्चों की देखभाल करना उनकी जिंदगी के सबसे अनमोल पलों में से एक है। उन्होंने लिखा, 'मैं रोज तुम्हारे पापा को लिखती हूं कि मुझे तुम तीनों से बात करने दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, तुम्हारा दिन कैसा रहा ये जानने के लिए मैं बहुत तरसती हूं।

विदेश

कुवैत ने नेतन्याहू की सीरिया यात्रा को बताया 'संप्रभुता का उल्लंघन'

कुवैत सिटी। कुवैत ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सीरिया दौरे पर घोर आपत्ति की है। कड़ी निंदा करते हुए इसे 'अवैध प्रवेश' करार दिया है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम सीरिया की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है।

जॉर्डन के अल-अज़्रक एयरबेस को क्यों निशाना बना रहा ईरान?

तेहरान। हाल के कुछ दिनों में ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब जॉर्डन को निशाने पर ले दिया है। ईरान ने जॉर्डन के मुवाफ्फक सलती एयरबेस पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि तेहरान इस अड्डे को जॉर्डन की सामान्य सैन्य संपत्ति के बजाय अमेरिकी सैन्य अभियानों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखता है।

अमेरिकी 'आर्थिक युद्ध' को ईरान ने बताया 'आर्थिक आतंकवाद', संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को लिखा पत्र

तेहरान। ईरान के खलिाफ चलाए जा रहे अमेरिकी 'आर्थकि युद्ध' को ईरान ने 'आर्थिक आतंकवाद' बताया। ईरान की 27 एयरलाइंस और नागरिक विमानन से जुड़ी संस्थाओं पर लगाए गए नए अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत गुलाम हुसैन दर्जी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष को पत्र लखिा।

राजदूत गुलाम हुसैन ने कहा कि ईरान के खलिाफ अपने मकसद में नाकाम रहने के बाद, अमेरिका ने आक्रामकता के एक वैकल्पिक तरीके के तौर पर आर्थिक दबाव का रास्ता अपनाया है। अमेरिका 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के जरिए आम नागरिकों के लिए जरूरी क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाकर और ईरानी जनता को अहम सामान और सेवाओं से वंचित रखकर उन्हीं मकसदों को

हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

ईरान की मेहर समाचार एजेंसी की रपिोर्ट के अनुसार, पत्र में दर्जी ने कहा कि इन प्रतिबंधों की वजह से नागरिक विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए जरूरी स्पेयर पाट्र्स, उपकरण, रखरखाव, मरम्मत, निरीक्षण और तकनीकी सेवाओं तक पहुंच में बाधा आती है। यह सभी नागरिक विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए बेहद जरूरी हैं।

उन्होंने कहा कि इसके कारण यात्रियों और विमानन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा पर अनावश्यक जोखिम बढ़ जाता है। साथ ही, लाखों आम नागरिकों की आवाजाही भी प्रभावित होती है।समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार, ईरानी राजनयिक ने कहा, ₹ये कदम तीन अक्टूबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की ओर से दिए गए आदेश की भी खुली अनदेखी हैं। अदालत ने स्पष्ट रूप से माना था कि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर नागरिक विमानन की सुरक्षा और उस पर निर्भर लोगों के जीवन पर पड़ सकता है।

अदालत ने अमेरिका से कहा था कि वह ईरान को नागरिक विमानन सुरक्षा के लिए जरूरी सामान और सेवाओं के निर्यात में आने वाली बाधाओं को हटाए।दर्जी ने कहा कि आर्थिक और वित्तीय उपायों का लगातार इस्तेमाल करना, जिसका उद्देश्य ईरान की आम जनता पर भारी कठिनाइयां और अभाव थोपकर राजनीतिक दबाव बनाना हो, आर्थिक आतंकवाद, सामूहिक सजा और मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर है।

उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन भी है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों का उल्लंघन भी शामिल है।समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार, ईरानी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से अपील की कि वे सभी सदस्य देशों से कहें कि वे अमेरिका की ओर से लगाए गए ऐसे एकतरफा प्रतिबंधों को न मानें और न ही उन्हें लागू करें, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ हों।उन्होंने विशेष रूप से उन प्रतिबंधों का जिक्र किया जिनसे आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर मानवीय नुकसान पहुंचता है या जिनके ऐसे नुकसान पहुंचाने की आशंका हो सकती है।

बांग्लादेश: जेल में बंद बेटे चिन्मय कृष्ण दास को देखे बिना मां ने त्यागे प्राण

ढाका। बांग्लादेश के प्रमुख हिंदू अधिकार नेता चिन्मय कृष्ण दास की मां का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा जेल में बंद बेटे से मिलने की थी लेकिन जेल प्रशासन ने पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। गुरुवार सुबह चटगांव जिले के हथजारी उपजिले में स्थित श्री श्री पुंडरीक धाम आश्रम में 71 वर्षीय संध्या रानी धर का निधन हो गया। उन्होंने मंगलवार को खुद उस आश्रम में जाने की इच्छा जताई थी, जहां उनका बेटा लंबे समय से रह रहा था।इससे पहले बीमार पड़ने पर उन्हें चटगांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने कैंसर की पुष्टि की थी। हालांकि, बांग्लादेश के बंगाली अखबार 'कालबेला' की रिपोर्ट के अनुसार, वह अस्पताल में नहीं रहना चाहती थीं।

पाकिस्तान के लिए मक्का समझौता 'रक्षात्मक गठबंधन', हूती विद्रोहियों पर हमले का इरादा नहीं

इस्लामाबाद। एक दिन पहले तक सऊदी अरब पर हूती के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात करने वाले पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। इस्लामाबाद ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ पिछले महीने हुए मक्का पैक्ट को एक रक्षात्मक गठबंधन बताया है और फिलहाल इसमें किसी अन्य देश को शामिल करने की कोई योजना नहीं है और न ही हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन का कोई इरादा है।

पाकिस्तानी विदेश कार्यालय प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि सऊदी अरब पर हूती हमले के बाद पाकिस्तान इस समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह पूरा करेगा। प्रवक्ता ने कहा, 'समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

नेपाल में बाढ़: परजिनों के डीएनए से होगी अपनों की पहचान, गुजरात से 29 सैंपल एकत्र

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने नेपाल में 26 अगस्त को आई वनिाशकारी बाढ़ के बाद उन लोगों के परजिनों का डीएनए सैंपल एकत्र कए हैं, जो इस त्रासदी में लापता हो गए। गुजरात के ऐसे करीब 30 लोग हैं जो बाढ़ का शकिार हो गए और अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। 30 में 29 लोगों को परजिनों को सैंपल इकट्ठा कर लए गए हैं।

इकट्ठा किए गए डीएनए सैंपल की प्रोफाइलिंग की जा रही है, ताकि आपदा में मिले शवों और मानव अवशेषों की पहचान की जा सके। बाकी एक लापता व्यक्ति के परिजनों से नमूने लेने की प्रक्रिया भी जारी है।गुजरात स्टेट नॉन-रेजिडेंट गुजराती फाउंडेशन (एनआरजीएफ), जो सामान्य प्रशासन विभाग के एनआरआई प्रभाग के तहत काम करता है, इस पूरी प्रक्रिया में परिवारों और भारत तथा विदेशों की संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।यह अभियान केंद्र

सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा है।

इसके तहत लापता लोगों के करीबी रिश्तेदारों के डीएनए नमूने लेने और उनकी प्रोफाइलिंग के लिए विशेष फोरेंसिक प्रयोगशालाएं तय की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के अनुसार इन निर्धारित प्रयोगशालाओं में डीएनए प्रोफाइलिंग का काम मुफ्त किया जा रहा है।गुजरात में इस प्रक्रिया के लिए छह प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जूनागढ़ और राजकोट में डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है।

गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) भारत में लिए गए डीएनए नमूनों की प्रोफाइलिंग और नेपाल में चल रही पहचान प्रक्रिया के साथ उसके मिलान को लेकर विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर रही है।एनएफएसयू की दस सदस्यीय फोरेंसिक टीम भी नेपाल में पहचान संबंधी प्रयासों में शामिल है। दूसरी ओर नेपाल पुलिस ने भी घटना के बाद मिले शवों और मानव अवशेषों की डीएनए जांच शुरू कर दी है।एनआरजीएफ प्रत्येक लापता व्यक्ति के परिजनों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहा है और उन्हें निर्धारित प्रयोगशालाओं, उपलब्ध सुविधाओं तथा डीएनए नमूने देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहा है।